RNI .NO. MPBIL / 2013/ 54381
डाक पंजीकरण संख्या MP/IDC/1619/2024-2026

संपादकः- डॉ. देवेन्द्र मालवीय

13 वर्ष

दैनिक सद्भावना पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

गणेश चतुर्थी पर्व की दैनिक सदभावना पाती परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं

www.sadbhawnapaati.com Email: sadbhawnapaatinews@gmail.com इंदौर, बुधवार ● 27 अगस्त , 2025 वर्षः-13 अंक -119 मूल्य -1 रु. कुल पृष्ठ - 8

राहुल-तेजस्वी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में तिरंगे का अपमान

● कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पैरों तले दिखा राष्ट्रीय ध्वज, रौंदते दिखे

सुपौल (एजेंसी)। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तिरंगे का अपमान होने के आरोप लगे हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान सुपौल के हुसैन चौक पर झंडे की लूट के दौरान तिरंगे का अपमान देखने को मिला। इस दौरान सड़क पर गिरे तिरंगे को कार्यकर्ता पैरों के तले रौंदते देखे गए। लेकिन किसी की नजर तिरंगे के अपमान पर नही गयी। हालांकि राहुल की वोट अधिकार यात्रा से सुपौल से निकलकर मधुबनी में प्रवेश कर चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उनके कई कैबिनेट सहयोगी मंगलवार को बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ' वोटर अधिकार यात्रा ' में शामिल होने पहुंचे। रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और दिल्ली में मौजूद अन्य मंत्री राष्ट्रीय राजधानी से बिहार पहुंचकर यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि वे बिहार में दरभंगा के पास राहुल तेजस्वी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर पुलिस के कथित बल प्रयोग की सोमवार को निंदा करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार को देश के युवाओं की चिंता नहीं है क्योंकि वह वोट चुराकर सत्ता में आई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी कथित बल प्रयोग की निंदा की।

मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी ही मरूंगा

डीके शिवकुमार बोले-मैंने भाजपा की टांग खींचने की कोशिश की

बेंगलुरु (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना वंदना गाने को लेकर विवाद के बीच कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को फिर से सफाई दी। उन्होंने कहा-मैंने उनकी (भाजपा) टांग खींचने की कोशिश की थी। मेरे कुछ दोस्त

इसका राजनीतिक दुरुपयोग करके भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवकुमार ने कहा-मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं और एक कांग्रेसी के रूप में ही मरूंगा। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के प्रति मेरी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर कांग्रेसियों और इंडिया ब्लॉक को मेरी टिप्पणी से ठेस पहुंची है, तो मुझे दुख है। मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूं। दरअसल, डीके शिवकुमार ने 21 अगस्त को संघ की प्रार्थना गीत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे की कुछ लाइनें गाई थीं।

बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने का इंतजार खत्म

सितंबर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, सम्राट चौधरी ने बताया

पूर्णिया/पटना (एजेंसी)। बिहार के लोग जिस पूर्णिया एयरपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, अब वो खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि पीएम मोदी हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे। उन्होंने यह घोषणा मंगलवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित भाजयुमो के कार्यक्रम में की। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर को राज्य के चौथे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पटना, दरभंगा और गया के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट से भी उड़ानें शुरू होंगी। सितंबर की शुरुआत में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (डीजीसीए) से मंजूरी मिलने की संभावना है। पूर्णिया हवाई अड्डे से 13 साल बाद फिर से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होंगी। साल 2012 में कुछ समय के लिए यहां सेवाएं शुरू हुई थीं, लेकिन अधूरी सुविधाओं और कम मांग के कारण उन्हें बंद कर दिया गया था। एयरपोर्ट निर्माण की प्रगति की समीक्षा की थी।

भाजपा अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे शिवराज!

संघ चीफ मोहन भागवत से मीटिंग के बाद अटकलें तेज

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर अब तक मुहर नहीं लग सकी है। साथ ही पार्टी की तरफ से कोई तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव

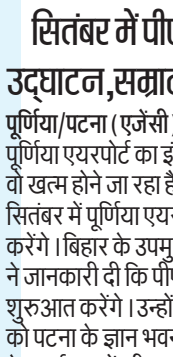

का शेड्यूल आने से पहले अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख प्रमुख मोहन भागवत के साथ केंद्रीय मंत्री की मुलाकात ने अटकलें तेज कर दी हैं। हालांकि, भाजपा की तरफ से आधिकारिक तौर पर साफ नहीं किया गया है कि अगले प्रमुख के नाम की घोषणा कब होगी। पार्टी आलाकमान की तरफ से उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गई है।

माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते पर लैंडस्लाइड

5 लोगों की मौत, यात्रा अस्थायी रूप से रोकी

डोडा में बादल फटा, 4 की मौत, 10 घर बहे

श्रीनगर (एजेंसी)। वैष्णो देवी में अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल भी हैं। रेस्क्यू जारी है। खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई

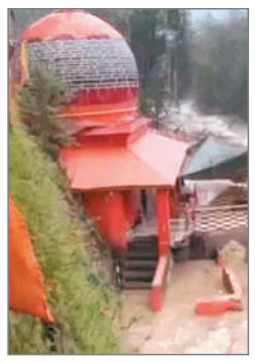

है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह जानकारी दी है। बोर्ड ने अभी इसके फोटो-वीडियो जारी नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण यह हादसा हुआ। भूस्खलन में कुछ लोगों के घायल होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं, भारी बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को कई जगहों पर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इसमें 10 से 15 घर बह गए। डोडा में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि, ये मौतें किन इलाकों में हुईं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। एक अधिकारी ने बताया कि दो लोगों की मौत घर गिरने से हुई, जबकि दो की मौत लगातार बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ में हुई। जम्मू-कश्मीर में लगातार तीन दिन से रुक-रुक कर भारी बारिश हो रही है। दो दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। कई सड़कें और रेल सेवाएं ठप हैं।

● नपा, नगरपरिषद अध्यक्ष का अविश्वास रोकने आएगा अध्यादेश

मध्यप्रदेश में पुलिस कर्मियों को विवेचना के लिए अब मिलेंगे टैबलेट

● कैबिनेट का फैसला, वन कोर्ट-वन प्रॉसीक्यूटर से भरेंगे 610 पद

भोपाल। प्रदेश में नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने से रोकने राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी। इसके जरिये निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शिकायतों के आधार पर पद से हटाने से रोका जा सकेगा। यह निर्णय मोहन यादव सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में लिया है। मोहन यादव सरकार ने तय किया है कि अब थानों में दर्ज होने वाले केस की जांच के लिए पुलिस के जांच अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे, जो जीपीएस कनेक्ट रहेंगे। सरकार ने एक अन्य प्रस्ताव में वन कोर्ट वन प्रॉसिक्यूटर नीति के अंतर्गत 610 नए प्रॉसिक्यूटर के पदों का सृजन करने का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार

प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। इसी तारतम्य में पुरानी व्यवस्था में शिकायतों के जरिये नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष को हटाने से रोकने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। अभी जो निर्वाचन व्यवस्था है, उसमें अराजकता की स्थिति बनती है। आर्थिक लेन देन भी होता है और विवाद की भी स्थिति बनती है।

● 75 करोड़ में 1732 टैबलेट खरीदने को मंजूरी- मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया को मजबूत बनाने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीएनएस की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत थानों को टैबलेट देने का फैसला किया है। ये टैबलेट लेकर जांच अधिकारी विवेचना और जांच के लिए जा सकेंगे। इन टैबलेट के जरिये वीडियो, फोटो लिए जा सकेंगे। हर टैबलेट जीपीएस से लैस होगा। पुलिस अनुसंधान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। शुरुआत में 1732 टैबलेट खरीदे जाएंगे। कुल 25 हजार टैबलेट खरीदे जाना है। इसके चलाने के लिए पुलिसकर्मी को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 75 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। शहरी क्षेत्रों में जहां अच्छी कनेक्टिविटी है, पहले वहां इसे चालू किया जाएगा। विजयवर्गीय ने कहा कि वन कोर्ट, वन प्रॉसीक्यूटर की नीति के अंतर्गत प्रॉसीक्यूटर बढ़ा रहे हैं।

नेवी में शामिल हुए आईएनएस उदयगिरि-आईएनएस हिमगिरि

दोनों स्वदेशी युद्धपोत, दुश्मन के रडार में नहीं आएंगे

अपनी ब्रह्मोस और बराक-8 जैसी मिसाइलों से लैस

मुंबई (एजेंसी)। इंडियन नेवी को मंगलवार को दो नए युद्धपोत आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि मिले।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, ये दोनों स्वदेशी जहाज हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बचे रहेंगे। इनकी तैनाती से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में होगी, जिससे नौसेना की ताकत बढ़ेगी। दोनों युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और भारत-इजराइल बराक-8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली से लैस है। इनमें 76 एमएम नौसैनिक बंदूकें और समुद्री युद्ध में पानी के अंदर चलने वाला टारपीडो विस्फोटक हथियार भी है। आईएनएस हिमगिरि को कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका नाम पुराने आईएनएस हिमगिरि से लिया गया है। आईएनएस उदयगिरि को मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरि पर्वत सीरीज के नाम पर रखा गया है, जो सिर्फ 37 महीनों में बना है। 18 जून को देश के पहले एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्णाला का कमीशन हुआ था। इसे विशाखापटट्नम में कमीशन किया गया था।

शी जिनपिंग करेंगे पीएम मोदी और पुतिन का व्यक्तिगत स्वागत

● एससीओ समिट से अमेरिका को संदेश या कोई नई चाल, चलेगा पता

बीजिंग (एजेंसी)। चीन और भारत जिस तरह से गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के स्वागत में रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, वो थोड़ा हैरान करने वाला है। नई दिल्ली में पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी का जोरदार स्वागत किया गया और अब चीन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूसी

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत तौर पर स्वागत करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत स्वागत करेंगे। पिछले सात सालों में ये पहला मौका होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री का चीन का दौरा होगा। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद फिर से दोनों देशों ने रिश्ते को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं।

भारत शांतिप्रिय देश लेकिन शांतिवादी नहीं

सीडीएस बोले-शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहें

मध्यप्रदेश के महू में कहा-ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है

महू (एजेंसी)। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान ने कहा कि भले ही भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन हम 'शांतिवादी' नहीं हैं। दुश्मन गलतफहमी में न रहे। देश की सेनाएं युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं। सीडीएस मंगलवार को मध्यप्रदेश के महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित रण संवाद-2025 कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के चीफ भी शामिल हो रहे हैं। सीडीएस ने कहा कि शक्ति के बिना शांति एक 'यूटोपियन' धारणा है। जनरल चौहान ने राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियां दोहराते हुए कहा, 'क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत, सरल हो।'

● ऑपरेशन सिंदूर जारी है, शस्त्र और शास्त्र एक साथ फॉलो करेंगे- सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर एक आधुनिक संघर्ष था, जिससे हमने कई सबक सीखे। उनमें से ज्यादातर पर अमल चल रहा है। सीडीएस ने कहा- गीता और महाभारत में युद्ध नीति के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। चाणक्य की नीति ने चंद्रगुप्त को विजय दिलाई। उन्होंने कहा है शक्ति, उत्साह और युक्ति... युद्ध नीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों को एकसाथ फॉलो करने की जरूरत है। जनरल चौहान ने कहा कि निकट भविष्य की जंग बेहद खतरनाक होगी, उसमें हम मिलकर लड़ेंगे।

दुनिया में अब 'मेड इन इंडिया' लिखी ईवी चलेगी

● मोदी बोले-मारुति की पहली ईवी को हरी झंडी दिखाई ● गुजरात के प्लांट से 100 देशों को की जाएगी निर्यात

अहमदाबाद (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी मंगलवार को गुजरात के हंसलपुर में ई-विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग-ऑफ किया। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है। ये गाड़ी पूरी तरह से भारत में ही बनी है और इसे 100 से ज्यादा देशों, जैसे यूरोप और जापान में निर्यात किया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ा है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। इस कार में 49 केवीएच और 61 केवीएच के दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन फरवरी-2025 से सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में हो चुका है। गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ रहा है। भारत को डेमोग्राफिक एडवांटेज है। हमारे पास स्किल वर्कफोर्स का बड़ा पूल है। जो हमारे हर पार्टनर के लिए विन-विन सिचुएशन बनाता है। जापान की सुजुकी कंपनी भारत में मैनुफैक्चरिंग कर रही है। जो गाड़ियां बन रही हैं वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही हैं। एक तरह से

मारुति सुजुकी कंपनी मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। पैसा किसी का भी लगे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे डॉलर हो या पॉन्ड हो या और करेंसी हो। लेकिन इससे जो प्रोडक्शन हो उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरे देश की मिट्टी की होगी। आज पूरी दुनिया, भारत की ओर देख रही है। ऐसे समय में कोई भी राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए। हर राज्य को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हिंदुस्तान आने वाले निवेशकों को इतना कन्फ्यूजन होना चाहिए कि वे सोचें, मैं इस राज्य में जाऊं या उस राज्य में। मैं सभी राज्यों को निमंत्रण देता हूं, आइए, रिफॉर्म की स्पर्धा करें, प्रो-डेवलपमेंट पॉलिसी की स्पर्धा करें और गुड गर्वनेंस की स्पर्धा करें। गर्व से स्वदेशी की ओर बढ़ चलें। मुझे आपका साथ चाहिए दोस्तों, 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। मारुति ई विटारा के 49 केवीएच बैटरी पैक वाले बेस मॉडल की कीमत 20 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। वहीं, हाई पावर वाली मोटर के साथ 61 केवीएच बैटरी पैक वाले मॉडल की कीमत 25 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) हो सकती है। इसके अलावा ऑल व्हील ड्राइव वर्जन की कीमत 30 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। भारतीय बाजार में ई विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी का मुकाबला टाटा कर्व और हुंडई क्रेटा और महिंद्रा 6 से रहेगा।

प्रदेश पाती

दैनिक सद्भावना पाती

इंदौर, बुधवार 27 अगस्त , 2025

एकता की मिसाल- प्रेमानंद महाराज को किडनी देने आगे आई मुस्लिम बेटी

नरसिंहपुर। जिले से एक अनूठी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है जिसने पूरे देश में आपसी भाईचारे और एकता की मिसाल पेश कर दी है। यहां मुस्लिम समुदाय की बेटी मेहनाज खान ने हिंदू संत प्रेमानंद महाराज के लिए अपनी एक किडनी दान करने का निर्णय लिया है। मेहनाज खान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नरसिंहपुर की ब्रांड एंबेसडर हैं और उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर के जरिए प्रेमानंद महाराज को पत्र भी भेजा है। मेहनाज खान का कहना है कि वह और उनका परिवार सोशल मीडिया के माध्यम से संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनते हैं। महाराज के विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है। संत प्रेमानंद महाराज हमेशा समाज में भाईचारे, अखंडता और प्रेम का संदेश देते हैं। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर मेहनाज ने यह बड़ा कदम उठाया है। उनका कहना है कि धर्म, जाति या मजहब से बढ़कर इंसानियत होती है और वही सच्चा हिंदुस्तानी है जो दूसरे के दुख-दर्द में साथ खड़ा हो। मेहनाज खान का यह कदम साबित करता है कि हिंदुस्तान की असली पहचान आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे में ही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रेमानंद महाराज एक सच्चे संत हैं और समाज को उनकी आवश्यकता है। इसलिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। मेहनाज खान की यह पहल न सिर्फ नरसिंहपुर बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई है। यह घटना आने वाली पीढ़ियों को भी यह संदेश देती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और जब बात प्रेम और भाईचारे की हो तो सभी सीमाएं मिट जाती हैं।

बाबा महाकाल की शरण में योगगुरु रामदेव

उज्जैन। मध्यप्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार, 26 अगस्त को एक विशेष क्षण देखने को मिला जब योगगुरु बाबा रामदेव बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। महाकाल की नगरी उज्जैन में रोजाना हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था लिए आते हैं और समय-समय पर राजनीति, खेल और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां भी बाबा महाकाल की शरण में पहुंचकर आशीर्वाद लेती हैं। इसी क्रम में योगगुरु रामदेव भी नंदी हॉल में भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। मंदिर पहुंचने पर बाबा रामदेव का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। मंदिर प्रबंधन समिति के उपप्रशासक एस.एन. सोनी ने उन्हें सम्मानित किया और बाबा को विशेष पूजन-अर्चन के लिए नंदी हॉल तक ले जाया गया। वहां उन्होंने भगवान महाकाल की आराधना की और ध्यान में लीन होकर भक्तिमय वातावरण का आनंद लिया। इस अवसर पर बाबा रामदेव ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने महाकाल मंदिर के विकास, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और भव्य दर्शन व्यवस्था के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश समृद्धि और प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। बाबा रामदेव ने भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हुए कहा कि महाकाल की असीम कृपा से सभी का जीवन सुखमय बने, किसी की अकाल मृत्यु न हो और भारत स्वस्थ, समृद्ध और विश्वगुरु के रूप में आगे बढ़े। मंदिर परिसर में बाबा की उपस्थिति से भक्तों में भी विशेष उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला।

दुष्कर्म पीड़िता ने लगाई फांसी, पीएम रिपोर्ट में नाबालिग निकली 2 महीने की प्रेग्नेंट, आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर। दुष्कर्म पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग 2 महीने की प्रेग्नेंट निकली है। घटना अधारताल थाना क्षेत्र की है।दरअसल, आरोपी ने नाबालिग का अगवा कर रेप किया था। उसके गर्भवती होने पर आरोपी उसे प्रताड़ित करने लगा था। जिससे तंग आकर उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।आरोपी ने 2 साल पहले शादी करने की बात कबूली थी। लेकिन शादी के बाद उसे गर्भवती कर दिया और प्रताड़ित करने लगा था। पड़ोसियों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी थी। जिसके बाद उनके पहुंचने पर पीड़िता फांसी के फंदे पर लटकती मिली थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।सीएसपी राजेश्वरी कौरव ने बताया कि 10 तारीख को एक सूचना मिली थी कि एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच में मालूम पड़ा कि मृतिका नाबालिग थी। जिसने 2 साल पहले किसी के साथ शादी की थी। घर वालों ने किसी तरह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। अपराध डेढ़ कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही चलानी कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व मंत्री के सरकारी बंगले में वारदात : चांदी की मूर्तियां और घरेलू सामान चोरी, मामला दर्ज

ग्वालियर। चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब चोरों के निशाने पर आम लोग ही नहीं बल्कि वीआईपी क्षेत्र भी आ गया है। शहर के रेसकोर्स रोड क्षेत्र, जिसे वीआईपी इलाका माना जाता है और जहां वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष का आवास है, वहीं स्थित पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के सरकारी बंगले में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार, चोरों ने बंगला नंबर 35 में सेंध लगाकर कीमती और घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूची चौंकाने वाली है, जिसमें दो चांदी की मूर्तियां, पंद्रह एल्युमिनियम के भगोने, दो बड़ी लोहे की कड़ाही, दो गैस सिलेंडर, पचास स्टील की थालियां, कुर्सियां और यहां तक कि नल की टोंटियां तक शामिल हैं। चोरी की शिकायत हैंशराज भदौरिया द्वारा पड़ाव थाना पुलिस में दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि आखिरी बार बंगले का ताला 12 अगस्त को खोला गया था। जब इसे दोबारा खोला गया तो अंदर का सारा सामान अस्त-व्यस्त और कई चीजें गायब मिलीं। यह घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि रेसकोर्स रोड को बेहद सुरक्षित और उच्चस्तरीय सुरक्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। बावजूद इसके, चोरों ने यहां आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम देकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में नौकरी का झांसा देकर 56 युवाओं से ठगी, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाए

सिवनी। एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है जिसने बेरोजगार युवाओं के सपनों को गहरी चोट दी है। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले दर्जनों युवाओं को ठगों ने शिकार बना डाला। मामला शासकीय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल से जुड़ा है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर 56 से अधिक युवाओं को ठगी का शिकार बनाया गया। जानकारी के मुताबिक रामदेव सिंह नामक व्यक्ति ने युवाओं को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उसने दस्तावेज़ प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर प्रत्येक से 2 से 3 हजार रुपये तक वसूल लिए। इतना ही नहीं, युवाओं को भरोसा दिलाने के लिए उसने बाकायदा फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिए। लेटर मिलने के बाद जब ये युवा मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां के अधिकारियों ने ऐसे किसी आदेश से साफ इनकार कर दिया और तब जाकर सारा मामला फर्जीवाड़ा साबित हुआ। अचानक ठगे जाने का एहसास होने पर पीड़ित युवाओं ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

जीतू पटवारी के बयान पर भड़के सीएम मोहन यादव, कहा कांग्रेस ने बहनों का अपमान किया, तुरंत मांगे माफी

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों महिलाओं को लेकर दिए गए बयानों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा हाल ही में दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्यप्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं और लाड़ली बहना योजना के नाम पर वोट लिए गए, अब राजनीतिक घमासान का कारण बन गया है। इस बयान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस का यह रवैया महिलाओं का सीधा-सीधा अपमान है और इसके लिए उन्हें तुरंत जनता और बहनों से माफी मांगनी चाहिए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है। हमारी सरकार ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आबादी के रूप में मानते हुए उनके लिए अलग-अलग योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण देकर यह साबित किया है कि बीजेपी महिलाओं के हक और अधिकारों को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी बहनों को न आरक्षण दिया और न ही उनके हित में कोई ठोस योजना बनाई। न तो लाड़ली लक्ष्मी योजना जैसी पहल की और न ही लाड़ली बहना जैसी जनकल्याणकारी

योजनाओं की शुरुआत की। उल्टा, कांग्रेस नेताओं द्वारा बार-बार अपमानजनक बातें कहना उनके मानसिक स्तर को दिखाता है। मुख्यमंत्री ने हरतालिका तीज का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पावन पर्व पर भी कांग्रेस के नेता ऐसी सोच रखते हैं, जो समाज की महिलाओं के प्रति अनादर को दर्शाता है। मोहन यादव ने कहा कि कभी कांग्रेस नेता बहनों को बोरे में भरकर पटकने की बात कहते हैं और अब उन्हें शराबी कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह न केवल निंदनीय है बल्कि पूरे मध्यप्रदेश की बहनों का अपमान है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से स्पष्ट शब्दों में माफी मांगने की मांग की और कहा कि बीजेपी सरकार बहनों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है और आगे भी महिलाओं के लिए नई ऊंचाइयों पर काम करती रहेगी।

श्रीकृष्ण को अपमानित करने वालों पर भड़की यादव महासभा, सात दिन में माफी नहीं तो होगा जबरदस्त आंदोलन

भोपाल। मध्यप्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई विवादित टिप्पणियों ने माहौल गर्मा दिया है। यादव महासभा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि उनके आराध्य का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। महासभा ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो लोग भगवान श्रीकृष्ण को ÷माखन चोर÷ या ÷वस्त्र चोर÷ कहने जैसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तत्काल ऐसी बातें बंद करनी होंगी और अगले सात दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यादव समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। यादव महासभा छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष प्रियेश यादव ने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियां न केवल भगवान श्रीकृष्ण की गरिमा पर चोट करती हैं, बल्कि पूरी सनातन संस्कृति और समाज की आस्था को भी आहत करती हैं। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण न तो माखन चोर थे और न ही वस्त्र चोर, बल्कि वे सत्य के रक्षक, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले और धर्म की स्थापना के लिए जीवन समर्पित करने वाले महायोद्धा थे। यादव समाज का इतिहास गौरवशाली है, और जो लोग इसे सहन नहीं कर पाते वही इस तरह की मनगढ़ंत और भ्रामक कहानियों का सहारा लेकर समाज को अपमानित करने की कोशिश करते हैं।

प्रियेश यादव ने आगे कहा कि सनातन परंपरा में भगवान श्रीकृष्ण से बड़ा कोई धर्म रक्षक और समाजसेवी नहीं हुआ। वे अनंत कलाओं के धनी, नीति और धर्म के उपदेशक तथा सच्चाई और धर्मनिष्ठा के प्रतीक थे। ऐसे महानायक का अपमान करना पूरे समाज के लिए असहनीय है। उन्होंने यह भी दोहराया कि यादव महासभा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समर्थन में मजबूती से खड़ी है और किसी भी सूरत में धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं होने देगी। महासभा ने सभी धर्मप्रेमी और सामाजिक बंधुओं से अपील की है कि ऐसे शब्दों और टिप्पणियों का प्रयोग करने वालों का बहिष्कार करें। यदि सात दिनों के भीतर माफी नहीं मांगी जाती तो यादव समाज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उनके सहयोगियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाएगा। इसमें उनके बंगले का घेराव, पुतला दहन और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शामिल होंगे।

दिल्ली में रबी कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज़: कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव का आह्वान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- उत्पादन बढ़े, लागत घटे और किसानों को मिले उचित दाम

ग्वालियर। देश में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए केंद्र सरकार अब रबी फसलों पर मंथन की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में आयोजित 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कार्यकर्ता गोष्ठी में हिस्सा लेते हुए जानकारी दी कि दिल्ली में 14 और 15 सितंबर को रबी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री, केंद्र सरकार के अधिकारी, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल होंगे। सभी मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि रबी सीजन में फसलों का बेहतर उत्पादन कैसे किया जाए और वैज्ञानिक रिसर्च को खेतों तक किस तरह पहुंचाया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की सेवा करना भगवान की पूजा करने के समान है। हमारा लक्ष्य है कि कृषि उत्पादन लगातार बढ़े, किसानों की लागत कम हो, उपज का उचित दाम मिले और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उन्हें समय पर राहत मिल सके। चौहान ने यह भी बताया कि कृषि का विविधीकरण बेहद जरूरी है ताकि धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न उत्पादन करती रहे। उन्होंने याद दिलाया कि एक समय ऐसा था जब भारत को अमेरिका से लाल गेहूं आयात करना पड़ता था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और किसानों व वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण पिछले 10 वर्षों में कृषि उत्पादन लगभग 44 प्रतिशत बढ़ा है। गेहूं उत्पादन ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से उत्पादन पर असर पड़ सकता है, इसलिए अब ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं जो इन चुनौतियों का सामना कर सकें। शिवराज सिंह चौहान ने जौ को भी एक महत्वपूर्ण फसल बताया। उन्होंने कहा कि जौ पोषण की दृष्टि से बेहद अहम है और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तापमान और पानी की कमी के बावजूद गेहूं व जौ की बेहतर पैदावार संभव हो सके, इस दिशा में वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। इसी सोच के साथ ग्वालियर में यह चिंतन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां प्रख्यात वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों ने मिलकर कृषि की नई दिशा पर विचार किया।

सीएम मोहन यादव ने बांटे 1060 युवाओं को नियुक्ति पत्र, बोले - अब 51 हजार पदों पर होगी भर्ती, कांग्रेस को बिजली संकट का ठहराया जिम्मेदार

भोपाल। रवींद्र भवन में एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विद्युत कंपनियों के 1060 नवचयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में चयनित युवा मौजूद रहे। समारोह में न केवल नियुक्ति पत्र सौंपे गए, बल्कि बिजली कंपनियों की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें प्रदेश की ऊर्जा क्षमता और विकास कार्यों की झलक दिखाई गई।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर को प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि आज जिन 1060 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, वे न केवल अपने भविष्य की नई शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को

और मजबूत बनाने में भी योगदान देंगे। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से काम करें और मध्यप्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।

सीएम ने अपने संबोधन में प्रदेश की बिजली व्यवस्था की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है जो 24 घंटे बिजली देने में सक्षम है। यहां तक कि दिल्ली मेट्रो भी मध्यप्रदेश से सप्लाई हो रही बिजली पर चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय बिजली की हालत इतनी खराब थी कि घरों और मोहल्लों में अंधेरा छाया रहता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बड़ा ऐलान किया कि बिजली विभाग में अब 51 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये भर्तियां होंगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने चयनित सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उनकी जिंदगी का नया अध्याय है और सरकार उनके साथ खड़ी है। अपने संबोधन के दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में बिजली विभाग पूरी तरह बदहाल हो चुका था और आम जनता अंधेरे में जीने को मजबूर थी। इसके उलट भाजपा सरकार ने न सिर्फ बिजली संकट को खत्म किया, बल्कि प्रदेश को बिजली के मामले में सरप्लस की ओर ले गई। उन्होंने कहा कि आज पड़ोसी देशों तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा हो रही है। यहां तक कि पाकिस्तान के नेता भी कहते हैं ङ्क काश मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते।

बिहार चुनाव में दिखेगा मध्यप्रदेश का दम, सीएम डॉ. मोहन यादव निभाएंगे बड़ी भूमिका, मंत्री और विधायक भी होंगे मैदान में सक्रिय

भोपाल। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और वहां सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनावी माहौल में अब मध्यप्रदेश की भी दमदार मौजूदगी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बिहार चुनाव में भाजपा की ओर से बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। वे न केवल वहां जनसभाओं और रोड-शो के जरिए जनता को संबोधित करेंगे, बल्कि संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ रणनीतिक बैठकें भी करेंगे। सूत्रों के अनुसार बिहार चुनाव को लेकर भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से विशेष चर्चा की है। इस दौरान तय किया गया कि बिहार चुनाव में मध्यप्रदेश संगठन पूरी ताकत झोंक देगा। पार्टी की रणनीति के तहत मध्यप्रदेश के कुछ मंत्रियों को बिहार की अलग-अलग विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया जाएगा। साथ ही प्रदेश के विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जाकर संगठन को मजबूत करें और भाजपा उम्मीदवारों को विजय दिलाएं। भाजपा का मानना है कि डॉ. मोहन यादव की लोकप्रियता, संगठनात्मक क्षमता और जोशपूर्ण नेतृत्व बिहार में भी असर दिखा सकता है। यही कारण है कि उन्हें बिहार चुनाव प्रचार का अहम चेहरा बनाया गया है। वहीं मध्यप्रदेश के मंत्री और विधायकों को भी चुनावी मैदान में सक्रिय कर संगठन की ताकत बढ़ाई जाएगी।

कीर समाज प्रतिभा सम्मान समारोह एवं महासम्मेलन उज्जैन में हुआ

सुरेंद्र कीर को युवा प्रदेश संयोजक बनाया, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्चुअल कार्यक्रम को किया संबोधित

भोपाल। आयोजित कीर समाज प्रतिभा सम्मान समारोह एवं प्रदेश कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी ने भोपाल से वर्चुअली संबोधित किया। एवं समाज को अस्वस्थ कराया की शीघ्र ही कीर समाज की एक राज्य स्तरीय पंचायत राजधानी भोपाल में आयोजित की जाएगी और समाज की विभिन्न समस्याओं का भी निवारण किया जाएगा कार्यक्रम उज्जैन सभापति श्रीमती कलावती जी यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ समाज के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह वानिया ने अपने संबोधन में अति शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर समाज की जटिल समस्या आरक्षण के समाधान हेतु मांग की जाएगी मां पूरी बाई कल्याण बोर्ड अध्यक्ष गया प्रसाद जी ने अपने संबोधन में समस्त नवनियुक्त पदाधिकारी को शुभकामनाएं प्रेषित की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद चौहान,भागीरथ दायमा,एन. पी. पटेल, मानसिंह पटेल, जे. पी.कीर ,तेजू बाबा, सुरेंद्र कीर, ने समाज को संबोधित किया सम्मेलन में प्रदेश के 24 जिलों से समाज उपस्थित हुई और 215 प्रतिभाओं का संगठन द्वारा सम्मान किया गया जिसमें प्रथम संजना कीर हाई स्कूल 96.6, द्वितीय निहारिका कीर 95.5 हाई स्कूल तृतीय प्रतिभा कीर ने स्थान प्राप्त किया प्रथम को लैपटॉप द्वितीय को टैबलेट एवं तृतीय को एंड्राइड मोबाइल देकर प्रतिभाओं का सम्मान किया नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी में सुरेंद्र कीर मंडीदीप को प्रदेश युवा संयोजक नियुक्त किया गया नियुक्ति के बाद सुरेंद्र कीर को प्रदेश अध्यक्ष कीर समाज कोमल सिंह वानिया, कीर कल्याण बोर्ड अध्यक्ष गया प्रसाद कीर प्रदेश संरक्षक एन.पी. पटेल एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ बड़ी संख्या में शुभकामनाएं प्रेषित की और सुरेंद्र कीर नेवी समाज को अस्वस्थ कराया की पूरी निष्ठा भाव के साथ समाज हित में काम करूंगा रामकिशोर कीर ने बताया कि बड़ी संख्या में रायसेन जिले से भी समाज बंधु पहुंचे जिसमें रमेश पटेल वरिष्ठ जिला अध्यक्ष ,सूरज कीर ,परशराम कीर , रमेश चंद कीर,नंदकिशोर जी सरपंच कीरत नगर, केवल कीर,बाला प्रसाद, हेमंत कीर युवा जिला अध्यक्ष,हिम्मत कीर ,चंदन कीर,मंगल कीर ,निर्भय कीर,आशीष कीर, आर्यन कीर,सूजन कीर, सचिन कीर,उत्तम कीर,मोहित कीर ,मुकेश पटेल,ज्ञान सिंह पटेल, रमेश पटेल,कारण कीर,गोलू कीर,आर्यन कीर ,विनोद कीर ,गौरव कीर, कपिल कीर,सुमित कीर, मुकेश कीर,मोहन कीर,सुनील कीर, हरीश कीर ,गौतम कीर,अशोक कीर,डॉक्टर मगन कीर,गंगा प्रसाद कीर, सीताराम कीर पूर्व जनपद सदस्य, उधम सिंह कीर, नरेश कीर, सरदार कीर उज्जैन पहुंचकर सम्मेलन में सम्मिलित हुए।

झूलेलाल चालीहा एवं अमर कथा पाठ का भव्य समापन

भोपाल। 40 दिन तक कठिन उपवास रखकर भगवान झूलेलाल की उपासना करने बाद इसके समापन के कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। संत हिरदाराम नगर सोमवार को भगवान झूलेलाल जी के 26वें वंशज ठकुर साईं मनीषलाल साहिब जी (साईं भरूचवारा) के आह्वान पर विश्वभर में चल रहे चालीहा साहब पर्व के अंतर्गत संत हिरदाराम नगर स्थित झूलेलाल ठकुर आसनलाल मंदिर बी वार्ड पुराना में आयोजित 40 दिवसीय सामूहिक अमर कथा पाठ का भव्य समापन हुआ।

संत हिरदाराम नगर पूज्य सिंधी पंचायत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत आसवानी जी ने जानकारी देते हो बताया की समापन अवसर पर पूज्य बहिराणा साहिब की महाआरती की गई, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, श्रद्धालु भक्तजन और संत समाज ने श्रद्धा और भक्ति भाव से भाग लिया। सभी श्रद्धालुओं ने पूज्य बहिराणा साहिब में अखा (आहुति) अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति तथा विश्व कल्याण हेतु भगवान झूलेलाल जी से प्रार्थना की।आरती उपरांत सामूहिक भोग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इसके पश्चात दोपहर 2 बजे पूज्य बहिराणा साहिब का विधि-विधान से शीतलदास बगिया तालाब पर विसर्जन किया गया। कार्यक्रम का सम्पूर्ण संचालन संयम, श्रद्धा और परंपरागत रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। इस धार्मिक अनुष्ठान ने समाज में भक्ति, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाया और भगवान झूलेलाल जी के दिव्य आशीर्वाद का अनुभव सभी भक्तों ने किया। इस मौके पर काफी संख्या में महिला पुरूष एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

दैनिक
सद्भावना पाती
...प्राणियों में सद्भावना हो...
इंदौर पाती

इंदौर, बुधवार 27 अगस्त , 2025

21 साल की छात्रा श्रद्धा तिवारी 2 दिन से लापता, जांच जारी

इंदौर। इंदौर से एक बार फिर रहस्यमयी गुमशुदगी का मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर को सकते में डाल दिया है। बहुचर्चित अर्चना तिवारी केस के कुछ ही दिनों बाद अब श्रद्धा तिवारी नाम की 21 वर्षीय युवती अचानक लापता हो गई है। यह मामला पुलिस और परिजनों दोनों के लिए चिंता का बड़ा सबब बन गया है। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा तिवारी इंदौर के गुजराती कॉलेज की छात्रा है। वह दो दिन पहले अचानक घर से निकली और तब से अब तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने बताया कि श्रद्धा अपना मोबाइल फोन भी घर पर ही छोड़कर गई है, जिससे उसकी लोकेशन या उससे संपर्क करना नामुमकिन हो गया है। गायब हुए उसे करीब 60 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। श्रद्धा के लापता होने के बाद परिजनों ने एमआईजी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। टीम ने छात्रा की गतिविधियों और संभावित संपर्कों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह मामला संवेदनशील है और हर एंगल से जांच की जा रही है। गौरतलब है कि इसी महीने 7 अगस्त को इंदौर की एलएलबी छात्रा अर्चना तिवारी अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। वह अपने भाई को राखी बांधने निकली थी लेकिन फिर घर नहीं लौटी। पूरे 12 दिन बाद अर्चना नेपाल बॉर्डर पर सकुशल बरामद की गई थी। इस घटना ने प्रदेशभर में सनसनी फैला दी थी। अब श्रद्धा की गुमशुदगी ने फिर से उसी केस की याद ताज़ा कर दी है। श्रद्धा तिवारी का मामला अभी शुरुआती चरण में है और पुलिस उसके दोस्तों, कॉलेज प्रशासन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी कभी बिना बताए घर से नहीं जाती, ऐसे में अचानक उसका इस तरह गायब हो जाना बेहद चौंकाने वाला है।

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को उम्रकैद: मां बयान से पलटी

इंदौर। इंदौर की जिला अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को पांच अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सविता जड़िया ने डीएनए रिपोर्ट और पीड़िता की आपबीती को आधार मानते हुए यह फैसला सुनाया।मामला 27 जुलाई 2022 का है, जब पीड़िता ने इंदौर के खुड़ैल थाने में अपने सौतेले पिता के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका सौतेला पिता उसे झोपड़ी में बुलाकर कई बार दुष्कर्म करता था और धमकी देता था कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे और उसकी मां को नुकसान पहुंचाएगा। आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की और उसका हाथ मोड़ दिया। अभियोजन के अनुसार, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2), 376(2)(एन), 376(3), 506, 323 और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान डीएनए रिपोर्ट ने आरोपी के अपराध को पुष्ट किया। हालांकि, सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां अपने बयानों से पलट गई और पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन डीएनए साक्ष्य और पीड़िता की गवाही के आधार पर कोर्ट ने सौतेले पिता को दोषी ठहराया। न्यायाधीश सविता जड़िया ने आरोपी को पांच धाराओं में आजीवन कारावास की सजा के साथ 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, पीड़िता को शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए प्रतिकर योजना के तहत 2 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा भी की गई।

आरटीओ इंदौर की कार्यवाही : राजकुमार ब्रिज, वल्लभनगर पर खड़ी 10 बसें जप्त

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर द्वारा लोक परिवहन वाहनों, बसों, स्कूल वाहनो सहित अन्य वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। झाबुआ टावर और पटेल ब्रिज पर बसों की सघन चेकिंग की गई। निरीक्षण के दौरान वाहनों के फ़िटनेस, परमिट, बीमा, पीयूसी, कर प्रमाण पत्र भी चेक किये गए । बसों में ओवरलोडिंग, अधिक किराया लेने की भी जांच की गई।। लोगों को अपने वाहनों पर एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। वाहन की गति, स्पीड गवर्नर सहित दस्तावेज की चेकिंग की जा रही है। दस्तावेज नहीं होने, क्षमता से अधिक सवारी पाए जाने, परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाली बसों, बेतरतीब खड़ी रहने वाली बसो पर कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान राजकुमार ब्रिज, वल्लभनगर पर बेतरतीब खड़ी पाई जाने पर 10 बसों को जब्त किया गया। साथ ही ट्रेवल्स, बस संचालकों से अपील की गई कि वह अपनी बसों को निर्धारित स्थान से ही चलाए अन्यथा बसें जब्त की जाएगी। बेतरतीब, निर्धारित स्थानों से भिन्न स्थानों से संचालित बसो की जब्ती की यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

हनीट्रैप के शिकार हुए शराब ठेकेदार भूपेंद्र रघुवंशी ने की आत्महत्या, आईफोन और 25 लाख ऐंठे फिर भी नहीं मान रही थी युवती

सुसाइड नोट में लिखा- गर्लफ्रेंड रेप केस की धमकी देती है

इंदौर। हनीट्रैप के शिकार होकर इंदौर के एक पब मालिक ने आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह उनका शव घर पर मिला। भूपेंद्र रघुवंशी ने जहर खाकर जान दे दी। आत्महत्या के पीछे हनीट्रैप की बात सामने आ रही है। पब मालिक भूपेंद्र रघुवंशी के पास से पुलिस को पांच पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें एक युवती का नाम लेकर लिखा है कि वह 25 लाख रुपये और आईफोन लेने के बाद भी ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देती थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। भूपेंद्र एक बार भी संचालित कर चुके हैं। उनके परिजनों ने पुलिस को बताया कि भूपेंद्र पिछले कुछ दिनों से तनाव में थे। किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। भूपेंद्र के परिवार में पत्नी, एक बेटा व एक बेटी है। तनाव में रहने के कारण वे कारोबार पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके तीन पब बंद हो गए थे। बाद में एक रेस्त्रां खोला। वह भी बंद हो गया था। कर्ज के कारण भी वे परेशान थे।

क्लब में हुई थी युवती से मुलाकात

पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी युवती से दो साल पहले भूपेंद्र की क्लब में ही मुलाकात हुई थी। महिला दूसरे शहर में रहती है, लेकिन इंदौर आती-जाती रहती थी। उसने भूपेंद्र से दोस्ती की और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और केस में फंसाने की धमकियां भी देने लगी। इसके बाद मंगलवार को भूपेंद्र ने आत्महत्या कर ली। भूपेंद्र इंदौर में लंबे समय से शराब कारोबार से जुड़े थे और दो पबों का संचालन भी कर चुके थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

भूपेन्द्र रघुवंशी, मृतक

इति तिवारी, आरोपी

सुसाइड नोट में लिखा– इति मुझे ब्लैकमेल कर रही थी

भूपेंद्र ने अपने पांच पन्नों के सुसाइड नोट में इति तिवारी नामक महिला का जिक्र किया और आत्महत्या के लिए उसे ही जिम्मेदार बताया। भूपेंद्र ने लिखा कि -'इति से मेरी दोस्ती दो साल पहले हुई थी। शुरू में सब ठीक ठाक चला। वह इंदौर में रहती थी, लेकिन बाद में मुंबई चली गई। वहां से उसने मुझे धमकियां देने शुरू कर दी। कहती थी कि दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दूंगी। एक दिन जब वह इंदौर आई तो उसने रात में खूब हंगामा किया। मामला 25 लाख रुपये में सुलझा। उसे कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे। उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उसके खर्चे मैं उठाता था। उसने मुझे पूरी तरह घर में कैद कर रखा था। भूपेंद्र ने आगे लिखा कि उसके लिए मैंने कार लेने की भी हां कर दी थी, लेकिन फिर इनकार किया तो उसने कहा कि केस लगवा दूंगी। उससे परेशान होकर मैंने दूसरा फोन लिया। एक फोन हमेशा उसके लिए फ्री रखना पड़ता था। उसके पति को भी हमारे बारे में पता था। एक बार मैं अपनी पत्नी और बच्चों को मुंबई छोड़ने गया था। तब भी इति ने ड्राइवर के सामने मुझसे झगड़ा किया। फिर वो इंदौर आई तो मेरे दोनों फोन को उसने कार के नीचे रखकर तुड़वा दिया। वो मुझे हर वक्त जलील करती थी। मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों और दोस्तों को कोई परेशान न करे।'

भाजपा महिला मोर्चा द्वारा राजवाड़ा पर किया गया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और राहुल गांधी का पुतला दहन

प्रदेश की मातृशक्ति पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर किया गया पुतला दहन

महिला मोर्चा ने प्रदेश की मातृशक्ति से माफी मांगने को कहा

इंदौर। कांग्रेस के प्रदेश पर अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा प्रदेश की मातृशक्ति पर दिए गए अभद्र बयान जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश की महिलाओं को सबसे ज्यादा शराब पीने वाली बताया है जो कि शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान है, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष श्रीमती शैलजा मिश्रा ने कहा कि हरतालिका तीज जैसे पावन अवसर पर जब देशभर की महिलाएं श्रद्धा और आस्था के साथ निर्जला व्रत रखती हैं, उस दिन प्रदेश भर कि मातृशक्ति का अपमान करना कांग्रेस की दूषित मानसिकता को उजागर करता है।क्या यही कांग्रेस की महिलाओं के प्रति असली सोच है क्या राहुल गांधी के इशारे पर जीतू पटवारी तीज जैसे पवित्र पर्व पर महिलाओं का घोर अपमान कर रहे हैं भारतीय संस्कृति और मातृशक्ति का अपमान करने वाली कांग्रेस की यह संकीर्ण व दूषित सोच प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। महिला मोर्चा ने मांग की है कि जीतू पटवारी को इस टिप्पणी के लिए सभी मातृशक्तियों से माफी मांगनी होगी।

इस अवसर पर भाजपा नगर महामंत्री श्रीमती सविता अखंड, महिला मोर्चा महामंत्री श्रीमती कंचन गिदवानी, उपाध्यक्ष श्रीमती वृंदा गौड़, नगर मंत्री श्रीमती अनीता व्यास, नगर मंत्री श्रीमती ज्योति पंडित, श्रीमती माधुरी जायसवाल,सुश्री रुपाली पेंढारकर, रंजना पिपले सरिता बहरानी,माया खिंची, हरविंदर कौर, परमजीत कौर, रेखा सेन, सरिता चौहान, मीरा मालवीय, रिंकी रायकवार, नफीसा बड़वानी वाला,सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।

मध्यप्रदेश में वेब जीआईएस 2.0 पोर्टल बना मुसीबत, पटवारियों ने दी चेतावनी -1 सितंबर से कामकाज ठप करने की तैयारी

इंदौर। किसानों और आम नागरिकों को भू-अभिलेख संबंधी सेवाएं ऑनलाइन मुहैया कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा हाल ही में लागू किया गया नया वेब जीआईएस 2.0 पोर्टल अब बड़े विवाद में घिर गया है। जिस सिस्टम को डिजिटल सुविधा और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था, वही अब पटवारियों और आम जनता के लिए सिरदर्द बन चुका है। पोर्टल के लगातार डाउन रहने और तकनीकी खामियों के कारण नामांतरण, बंटवारा, आदेश पर अमल, डायवर्शन, नक्शा विभाजन और केवाईसी जैसे जरूरी काम ठप हो गए हैं। किसानों को खसरा, बी-1 और नकल जैसी सेवाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं। बीते कई दिनों से प्रदेशभर में इस पोर्टल के सुचारू रूप से न चलने की वजह से न केवल किसान बल्कि खुद पटवारी भी परेशान हैं। बार-बार सर्वर डाउन होने और प्रक्रिया के बीच तकनीकी गड़बड़ी आने से काम अधूरा रह जाता है। परिणामस्वरूप सीएम हेल्पलाइन पर लगातार शिकायतें दर्ज हो रही हैं और जिला स्तर पर समीक्षा के दौरान पटवारियों को दंडित भी किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में असंतोष गहराता जा रहा है। पटवारी संघ का कहना है कि इस पोर्टल के शुरू होते ही उन्होंने इसके विरोध में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन शासन-प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। पहले वर्जन की तरह ही नया वर्जन 2.0 भी यूजर फ्रेंडली साबित नहीं हुआ। अब संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 1 सितंबर तक इस पोर्टल की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे इसका उपयोग पूरी तरह बंद कर देंगे। हालांकि सामान्य कार्य जारी रहेंगे, लेकिन वेब जीआईएस पोर्टल का बहिष्कार किया जाएगा।

गौरतलब है कि हाल ही में तहसीलदार भी अपनी मांगों को लेकर 13 दिन तक विरोध पर बैठे थे, जिसके कारण बड़ी संख्या में फाइलें पेंडिंग हो गई थीं। अब उन फाइलों को निपटाने में तेजी लाई जा रही है, वहीं पटवारियों का आंदोलन सरकार के लिए नई चुनौती साबित हो सकता है। किसानों और आम जनता की सुविधा के लिए लागू किए गए इस पोर्टल की खामियां अब शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं। यदि समय रहते तकनीकी सुधार नहीं किए गए तो प्रदेश में भू-अभिलेख संबंधी कार्य पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं और इससे आम लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी।

इंदौर नगर निगम के इंजीनियरों के प्रयोगों से फिर चर्चा में डीआरपी लाइन चौराहा, तीन साल बाद भी काम अधूरा

इंदौर। नगर निगम के इंजीनियरों के कामकाज पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। तीन साल पहले डीआरपी लाइन चौराहा (शांतिपथ चौराहा) को व्यवस्थित करने और यातायात को सुगम बनाने के नाम पर वहां बनी विशाल रोटरी को तोड़ दिया गया था। उस समय तर्क दिया गया था कि रोटरी के छोटे होने से वाहनों का आवागमन और बेहतर ढंग से हो सकेगा। कई दिनों तक मशक्कत कर रोटरी को छोटा किया गया, लेकिन अब निगम ने फिर से उसी स्थान पर उतनी ही बड़ी रोटरी बनाने का काम शुरू कर दिया है। शहरवासी सवाल उठा रहे हैं कि जब अंत में बड़ी रोटरी ही बनानी थी, तो पहले वाली रोटरी क्यों तोड़ी गई। इस काम में न केवल समय और संसाधनों की बर्बादी हुई, बल्कि यातायात व्यवस्था भी लगातार प्रभावित होती रही। सौंदर्यीकरण के नाम पर लगाए गए पेवर ब्लॉक और फुटपाथ तो तैयार हो गए, लेकिन मूल उद्देश्य यानी यातायात सुधार अब भी अधूरा है। नगर निगम का यातायात प्रकोष्ठ लंबे समय से ऐसे ही उलझे हुए प्रयोगों को लेकर चर्चा में रहता है। चंदन नगर क्षेत्र में बिना किसी प्रस्ताव या स्वीकृति के गलियों और सड़कों के नाम बदलकर बोर्ड लगा दिए गए थे, जिसके चलते कई अधिकारी जांच के घेरे में आ गए। वहीं, शहर के अन्य चौराहों पर भी अधूरे कामों की भरमार है। रामबाग की ओर जाने वाले चौराहे को संवारने का काम लंबे समय से अटका हुआ है। एमजी रोड थाने का पुराना भवन तोड़े बिना लेफ्ट टर्न चौड़ा करने की योजना भी ठंडे बस्ते में है। निगम की यह कार्यशैली आम नागरिकों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है।

नौलखा स्थित आर.के. हॉस्पिटल की लापरवाही उजागर, मृतक बेटी के इलाज के नाम पर परिजनों से वसूले रुपए, FIR दर्ज

इंदौर। शहर के नौलखा चौराहे पर स्थित आर.के. हॉस्पिटल एक बड़े विवाद में घिर गया है। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने न केवल इलाज में गंभीर लापरवाही बरती बल्कि मरीज की मौत के बाद भी परिजनों को बाहर से दवाइयाँ लाने भेजा। मृतका छाया जायवाल (उम्र 22 वर्ष) के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका के पिता रमेश जायवाल ने बताया कि उन्होंने 5 दिन पहले अपनी बेटी को सांस की बीमारी (अस्थमा) के इलाज के लिए आर.के. हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान अब तक करीब 80 हजार रुपए खर्च हो चुके थे। मंगलवार सुबह उन्होंने बेटी को नाश्ता करवाया था, लेकिन दोपहर में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल की टीम उसे आईसीयू में ले गई। इस दौरान पिता को बताया गया कि अस्पताल में बिजली नहीं है और उनकी बेटी का इलाज किया जा रहा है।

रमेश जायवाल के मुताबिक, इसी बीच उन्हें अस्पताल प्रबंधन ने बाहर से दवाइयाँ लाने भेज दिया। जब वे दवाइयाँ लेकर लौटे तो उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने दावा किया कि इलाज के दौरान ऑक्सीजन मास्क लगाकर प्रयास किए गए, लेकिन बेटी को बचाया नहीं जा सका। हालांकि, जब परिजनों ने अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज देखा तो मामला डॉक्टरों और स्टाफ की बातों से उलट निकला और लापरवाही के संकेत साफ दिखाई दिए। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने थाना संयोगितागंज में अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि यह सिर्फ इलाज में लापरवाही नहीं बल्कि सीधा-सीधा धोखाधड़ी और पेशेवर जिम्मेदारी से खिलवाड़ है।

इंदौर: उत्कृष्ट कार्य करने वाले 52 पुलिसकर्मी सम्मानित

ड्रग तस्करी, अपहरण, अंधे कत्ल और यातायात प्रबंधन में दिखाया साहस, पुलिस आयुक्त ने प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार देकर किया सम्मान

इंदौर। पुलिसिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में साप्ताहिक पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार 26 अगस्त को पलासिया स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 52 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार करने वाली टीम सम्मानित – समारोह में सबसे पहले अपराध शाखा की टीम को सम्मानित किया गया जिसने एक महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर 516 ग्राम ब्राउन शुगर, 48.50 लाख रुपये नगद और अन्य सामग्री सहित कुल 1.50 करोड़ रुपये का मशरूका जब्त किया था। इस कार्रवाई में एसीपी अपराध देवेंद्र सिंह धुर्वे, निरीक्षक जितेंद्र चौहान और टीम के 19 सदस्य शामिल थे।

अपहरण, अंधे कत्ल और डकैती के मामलों में सफलता –थाना आजाद नगर और मल्हारगंज पुलिस की टीम को अपहर्ता की दस्तयाबी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सम्मानित किया गया। वहीं थाना हीरानगर की उपनिरीक्षक अंजू बक्शी को पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में सराहनीय कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया। थाना चंदन नगर और द्वारकापुरी की टीम ने अंधे कत्ल का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि थाना संयोगितागंज के प्रआर कालीचरण को डकैती के मामले में 8 आरोपियों को पकड़ने पर सम्मानित किया गया।

गुमशुदगी और कानून व्यवस्था में योगदान – थाना बाणगंगा के प्रआर नानूराम चावड़ा को 10 गुमशुदा नाबालिग बच्चों की दस्तयाबी और जनजागरूकता कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं खजराना, एमआईजी, परदेशीपुरा, विजय नगर और लसूडिया थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों को कानून व्यवस्था ड्यूटी में बेहतर योगदान के लिए प्रशंसा मिली।

यातायात व आसूचना शाखा का सम्मान – यातायात पुलिस के सउनि रमेश चंद्रवंशी और सैनिक मूलचंद कटारिया को चैन स्नैचिंग के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुरस्कृत किया गया। सउनि लालसिंह भंडारी, गजेंद्र सिंह तोमर और महिला आरक्षक निर्मला मेवाड़ा को पीक ऑवर्स में बेहतर यातायात प्रबंधन हेतु सम्मानित किया गया। इसके अलावा आसूचना व सुरक्षा शाखा के 4 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को भी सत्यापन और सूचना संकलन कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया।

पुलिस आयुक्त ने बढ़ाया मनोबल – पुलिस आयुक्त सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम पुलिसकर्मियों के मनोबल को ऊंचा रखने का प्रयास है। जब मेहनत और निष्ठा को सम्मान मिलता है तो पुलिसकर्मी और अधिक ऊर्जा से कार्य करते हैं। उन्होंने सभी से आगे भी इसी तरह लगन और जिम्मेदारी से काम करने का आह्वान किया।

इंदौर में जल्द दिखेगी डबल डेकर बस, दिवाली से पहले शुरू होने की उम्मीद

इंदौर। शहरवासियों को जल्द ही डबल डेकर बस में सफर करने का मौका मिलने वाला है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने डबल डेकर बस का ट्रायल पहले ही पूरा कर लिया है और अब कंपनी खुद बस खरीदकर उसे बस ऑपरेटर को संचालन के लिए देगी। दरअसल, इससे पहले दो बार टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन किसी भी बस ऑपरेटर ने बस खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। अब कंपनी ने तय किया है कि वह स्वयं बस खरीदेगी और फिर ऑपरेटर को सौंपकर इसका संचालन करवाएगी। मुंबई से मंगाई गई बस का ट्रायल शहर के विभिन्न मार्गों पर किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि कई रूट पर बस आराम से संचालित हो सकती है। इसके बाद 7 ऐसे मार्गों को चुना गया है, जहां बस की ऊंचाई और सड़क की स्थिति को देखते हुए इसे चलाना संभव होगा। अनुमान है कि बीआरटीएस या अन्य उपयुक्त रूट पर इसका संचालन किया जा सकता है।

अनंत चतुर्दशी पर कलाबाजी दिखाने की होड़ शुरू

इंदौर। शहर में गणेश चतुर्थी की तैयारी प्रारम्भ हो चुकी है। आज जगह-जगह भगवान गणेश की स्थापना होगी। वही शहर के प्रमुख अखाड़ों में अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले चल समारोह को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर बच्चों से लेकर युवा तक अपनी कलाबाजी सीख रहे हैं। शहर की पहचान बनी अनंत चतुर्दशी की झांकी के साथ अखाड़ों की अपनी अलग पहचान है। सभी अखाड़े अपनी अपनी कलाओ में पारंगत है।

वहीं अपने अपने अखाड़ों के प्रदर्शन को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। शहर के ऐसे ही अखाड़े महावीर व्यायाम शाला में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अखाड़े के गिरीराज नीमा ने बताया कि खलीफा प्रवीण पहलवान और जगदीश के नेतृत्व में अखाड़े में बड़ी संख्या में बच्चे बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। इसमें सैकड़ों बच्चियां भी कलाबाजी सीख रही है। 400 से अधिक बच्चे तलवारबाजी, बनेटी, पटा, बंदिश, गत्ताफरी, झूमर चलाना सीख रहे हैं। इतवारिया बाजार से निकलने वाले अखाड़े में इंदिरा नगर में कलाबाजी सिखाई जा रही है। सभी बच्चे जोश से भरे अपने अखाड़े को नंबर वन लाने के लिए प्रयासरत हैं। सुबह-शाम बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ ये कलाबाजी सीख रहे हैं।

दैनिक सद्भावना पाती
इंदौर, बुधवार 27 अगस्त , 2025

प्रदेश के 100% विद्यालयों में 'हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान' कार्यक्रम 1 सितंबर को

संकल्प वाचन के पोस्टर का विमोचन स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने किया

भोपाल। प्रदेश के 100% विद्यालयों में 'हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान' कार्यक्रम 1 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सानिध्य में संपन्न होगा। हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान के संकल्प वाचन के पोस्टर का विमोचन दिनांक 26 अगस्त को मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के मंत्र द्वारा मंत्रालय में किया गया द्य इस अवसर पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर क्षत्रवीर सिंह राठौर, संभागीय अध्यक्ष विकास सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष नागेश पांडे, संभागीय संगठन मंत्री देवी दयाल भारती, सह संगठन मंत्री राजीव शर्मा, प्रांतीय सचिव संध्या नाइक, जिला सचिव बालेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष जितेंद्र चौहान महानगर, विकासखंड एवं तहसील पदाधिकारिओं में, श्रीमती अर्चना शर्मा, अवनीश श्रीवास्तव, दिनेश शुक्ला, लाखन सिंह सिंगर, चंद्रेश चौहान, पवन शर्मा, नेहा कश्यप, मीडिया सहायक हीरानंद नरवरिया, डॉ वीरेंद्र चौरसिया समेत पदाधिकारी मंत्रालय में सहभागी हुए द्य प्रदेश अध्यक्ष डॉ राठौर ने बताया संपूर्ण देश में 5 लाख से अधिक विद्यालयों में एवं प्रदेश के लगभग एक लाख विद्यालयों में एक सितंबर को यह कार्यक्रम प्रार्थना के समय आयोजित किया जाने वाला है जिसमें विद्यालयों के लाखों शिक्षक एवं करोडों छात्र मिलकर साझा संकल्प लेंगे कि उन्हें अपने-अपने विद्यालय पर गर्व है और हम अपने विद्यालय को शैक्षणिक गुणवत्ता से परिपूर्ण करते हुए, छात्रों में नैतिक एवं चारित्रिक संस्कारों का समावेश करेंगे, चाहे पर्यावरण अथवा नवाचार हो, महापुरुषों की जीवन गाथाएं हों एवं जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे उनके आधार पर हम अपने विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम बनाकर परीक्षा परिणाम भी 100त्न लाकर प्रत्येक छात्र को सामाजिक सरोकार तथा अपने देश एवं समाज के प्रति संवेदनशील बनाएंगे। इस अवसर पर पोस्ट का विमोचन करते हुए राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश में बहुत अच्छा संदेश देने वाला है जहां छात्र और शिक्षक मिलकर अपने विद्यालय को अच्छे से अच्छा बनाने का संकल्प लेंगे और प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाते हुए और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए विद्यालय परिसर को हरा भरा रखकर परीक्षा परिणाम भी उत्कृष्ट देने का प्रयत्न करेंगे। यह शिक्षा जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।

हाईकोर्ट का स्पष्ट रुख, रेस्तरां अपने बिल में अलग से नहीं जोड़ सकते सेवा शुल्क

शहरों-महानगरों में महंगे रेस्तरां में भोजन के लिए जाने वाले ज्यादातर लोग शायद इस बात पर बहुत गौर नहीं करते कि वे कितने पैसे चुका रहे हैं। यही वजह है कि रेस्तरां में खाने-पीने के कुल खर्च के अलावा भी अलग से सेवा शुल्क जोड़ दिया जाता है। या तो लोग इसके औचित्य से अनजान रहते हैं या फिर उसे चुकाने में उन्हें कोई उज्र नहीं होता। जबकि यह सीधे-सीधे उपभोक्ता अधिकारों का हनन है और किसी वस्तु की निर्धारित से ज्यादा कीमत वसूलने का अवांछित प्रयास है। इसे कानूनन भी गलत माना जाना चाहिए। हालांकि इस तरह अनधिकृत रूप से ज्यादा कीमत वसूलने के मुद्दे पर पहले भी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि रेस्तरां अपने बिल में अलग से सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते। अदालत ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को सबसे अहम बताया था। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि ग्राहकों से नाहक पैसे वसूलने के मसले पर रेस्तरां मालिक क्यों अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। अब एक बार फिर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेस्तरां एसोसिएशन से यह पूछा है कि जब आप खाने-पीने की चीजों पर पहले से ही अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा शुल्क वसूल रहे हैं, तब फिर अलग से सेवा शुल्क क्यों ले रहे हैं। यह जगजाहिर हकीकत है कि किसी भी महंगे रेस्तरां में अगर कोई व्यक्ति भोजन करने जाता है तो उसे वहां मिलने वाले खाद्य पदार्थों के लिए वाजिब से काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। अतिरेक तब हो जाता है, जब रेस्तरां की ओर से न केवल सामान्य कीमतों से अधिक मूल्य पर वस्तुएं दी जाती हैं, बल्कि खाना परोसने के नाम पर कुल बिल में अलग से सेवा शुल्क भी जोड़ दिया जाता है।सवाल है कि क्या ग्राहकों के सामने यह स्पष्ट किया जाता है कि रेस्तरां में उनकी सीट पर खाने-पीने का सामान पहुंचाने के लिए अलग से पैसे जोड़े जाएंगे। यही नहीं, आमतौर पर बिल चुकाने के बाद रेस्तरां या होटल के बैरे को बख्शीश देना भी एक रिवायत-सी बन चुकी है। इस तरह, ऐसे होटलों या रेस्तरां में कुल खर्च के ऊपर भी कई बार खासी रकम चुकानी पड़ती है। ऐसी वसूली पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और दिल्ली उच्च ने रेस्तरां एसोसिएशन के रुख पर वाजिब सवाल उठाया है।

आज का कार्टून

जेल से शासन पर लगेगा पूर्णविराम!

भारतीय लोकतंत्र की सबसे संवेदनशील धुरी 'नैतिक वैधता' तभी टिकाऊ बनती है जब सार्वजनिक पद पर बैठे लोग कानून के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप ही आचरण करें। 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 इसी कसौटी को संस्थागत रूप देता है। यह निर्णय दोषसिद्धि से पहले 'सत्ता के नैतिक मानदंड' की रक्षा करता है। ठीक उसी तरह जैसे सिविल सेवाओं में 48 घंटे से अधिक की हिरासत पर 'डीम्ड सस्पेंशन' लागू हो जाता है। चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए भी 30 दिन की ऊंची सीमा और पांच वर्ष सजा की दहलीज तय करके विधेयक ने मनमानेपन की आशंका को भी सीमित किया है। ऐसे कदम का भी सदन में विरोध होना समझ से परे है जबकि इस बिल को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक रूप से नैतिक तर्क के साथ रखा है।

अमित शर्मा

विधेयक तीन संवैधानिक प्रावधानों अनुच्छेद 75, 164 और 239एए में संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके तहत प्रावधान होगा कि कोई भी केंद्रीय या राज्य मंत्री या दिल्ली का मंत्री, यदि लगातार तीस दिन हिरासत में रहे और मामला ऐसा हो जिसमें सजा पांच वर्ष तक या उससे अधिक का प्रावधान है तो राष्ट्रपति/राज्यपाल संबंधित मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन उसे पद से हटा देंगे। यदि किसी मंत्री की बर्खास्तगी की सलाह 31वें दिन तक नहीं आती तो भी वह अगले दिन स्वतः पद से मुक्त हो जाएगा। यदि स्वयं प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री ऐसी ही स्थिति में हों तो उन्हें भी 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा अन्यथा वे अगले दिन पद पर बने नहीं माने जाएंगे। साथ ही, बिल यह भी स्पष्ट करता है कि हिरासत से रिहाई पर ऐसे व्यक्ति को पुनर्नियुक्ति की कानूनी गुंजाइश बनी रहती है। यह सूक्ष्म संतुलन तात्कालिक नैतिक जवाबदेही और भविष्य में पुनर्वास की संभावना कानून के शासन तथा जन-विश्वास दोनों की रक्षा करता है।

प्रस्ताव से साफ है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, जिसके लिए पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है तो वह पद पर बना नहीं रह सकता। इस विधेयक के साथ केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू-कश्मीर के लिए समान प्रावधान वाले दो साधारण संशोधन विधेयक भी रखे गए हैं, जिससे नियम पूरे देश में एकरूप हो जाते हैं। विधेयक के 'वस्तुपत्र एवं कारण' में सरकार साफ कहती है कि गंभीर आरोपों में हिरासत में गया मंत्री संवैधानिक मर्यादा, सुशासन और जनता के भरोसे को ठेस पहुंचा सकता है इसलिए पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह दंड नहीं बल्कि शासन-नीति सुरक्षा उपाय है।

केंद्र के समान ढांचा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) विधेयक, 2025 के माध्यम से भी प्रस्तावित है। इन दोनों में वही 30 दिन-5 वर्ष वाली कसौटी रखी गई है और मुख्यमंत्री/मंत्री के हटाए जाने की वही प्रक्रिया लागू होगी। इस तरह किसी भी भौगोलिक अथवा संवैधानिक इकाई में 'अपवाद' नहीं बचेगा और आचरण का एक सामान्य, स्पष्ट तथा पूर्व-निर्धारित मानक स्थापित होगा।

लोकसभा में तीखी बहस और हंगामे के बीच यह संवैधानिक संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा जा चुका है। यह समिति लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्यों की होगी, जिन्हें क्रमशः स्पीकर और सभापति नामित करेंगे। सरकार ने समिति से आग्रह किया है कि वह अगली संसदीय बैठक के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट दे यानी स्क्रूटनी तेज, तथ्यों-तर्कों पर आधारित और समयबद्ध हो। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि जेपीसी की सिफारिशें परामर्शात्मक होती हैं वे बाध्यकारी नहीं, पर परंपरा यही रही है कि सरकार गंभीर आपत्तियों/सुझावों पर संशोधन-प्रस्ताव लाती है।

यह कहना आवश्यक है कि विधेयक जनप्रतिनिधि के मूलाधिकारों या मतदाता-प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं तोड़ता वह केवल मंत्री के पद पर बने रहने की शर्तें स्पष्ट करता है। अभियोजन लंबित रहते हुए गिरफ्तारी और लंबी हिरासत में सत्ता-प्रयोग के साथ निहित 'हितों के टकराव' को यह व्यावहारिक रूप से संबोधित करता है। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान यह दर्शाता है कि बिल दोषसिद्धि से पहले 'कैरियर-एक्सक्लूजन' नहीं करता सिर्फ शासन को संदेह से मुक्त रखने की प्राथमिकता तय करता है। यही संतुलन इसे दंडात्मक कानून के बजाय नैतिक-प्रशासनिक साधन बनाता है।

विपक्ष की दलील है कि गिरफ्तारी राजनीतिक हो सकती है, 30 दिन की हिरासत किसी भी एजेंसी के दुरुपयोग से हासिल की जा सकती है। वस्तुतः, बिल इस आशंका को दो स्तरों पर सीमित करता है। पहला, 'गंभीर अपराध' की परिभाषा पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामलों तक सीमित है, दूसरा हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक है और राष्ट्रपति/राज्यपाल का औपचारिक आदेश प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की सलाह पर ही होता है यानी निर्वाचित नेतृत्व की जवाबदेही और अनुशासन साथ-साथ चलते हैं। तुलना के लिए याद रखें कि शासकीय सेवाओं में तो 48 घंटे की हिरासत पर स्वतः निलंबन लागू होता है। यहां 30 दिन की लम्बी, न्यायिक निगरानी वाली हिरासत का पैमाना रखा गया है यह कहीं अधिक सख्त प्रक्रिया-सुरक्षा है।

तमिलनाडु के वी. सेंथिल बालाजी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने बेल के दौरान मंत्री-पद और निष्पक्ष जांच/गवाहों पर दबाव जैसे सवालों को लेकर सख्त टिप्पणियां कीं। अंततः मंत्री-पद छोड़ना और जमानत बचाना दोनों में से चुनाव करना पड़ा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हिरासत के दौरान पद बनाम प्रक्रिया की बहस भी इसी नैतिक बिंदु पर आकर टिकती रही। इन घटनाओं ने जनचर्चा में यह प्रश्न स्थायी रूप से दर्ज कर दिया कि जब कोई नेता न्यायिक हिरासत में हो तो क्या वह शासन-प्रक्रिया का निर्विघ्न संचालन कर सकता है। नया बिल इसी व्यावहारिक दुविधा का संवैधानिक समाधान है।

जेपीसी अब विभिन्न हितधारकों संवैधानिक विशेषज्ञों, बार काउंसिल, राज्य सरकारों, पूर्व न्यायाधीशों व पुलिस, जांच एजेंसियों से साक्ष्य लेकर प्रावधानों की भाषा को और कस सकती है। उदाहरण के लिए, लगातार तीस दिन की गणना, 'जमानत' और 'न्यायिक हिरासत' के बीच सीमा-रेखा और 'पुनर्नियुक्ति' के समय जैसे बिंदुओं पर अधिक स्पष्टता संभव है। समिति की रिपोर्ट आते ही सरकार आवश्यक संशोधनों सहित बिल को विशेष बहुमत के लिए पुनः सदन में ला सकती है। इस पूरी प्रक्रिया से स्पष्ट है कि यह कदम विपक्ष सहित भविष्य की किसी भी सरकार पर समान रूप से लागू होगा अर्थात यह कदम 'विनर-टेक्स-ऑल' की राजनीति नहीं बल्कि 'रूल्स-टेक-ऑल' का लोकाचार स्थापित करता है।

बिल का स्वरूप 'डिस्क्वालिफिकेशन' नहीं बल्कि 'ऑफिस-होल्डिंग' का अस्थायी नियमन है। यह विधायिका/न्यायपालिका/कार्यपालिका के शक्तिसंतुलन को प्रभावित किए बिना 'संवैधानिक नैतिकता' को लागू करता है। गंभीर अपराध, न्यायिक हिरासत और 30 दिन जैसी वस्तुगत कसौटी इसे 'मनमाना' होने से बचाती है। साथ ही पुनर्नियुक्ति का विकल्प इसे 'स्थायी दंड' में तब्दील नहीं होने देता। यह कहा जा सकता है कि यह कानून न्यायिक जांच में और अधिक मजबूती से खड़ा होगा। इस दिशा में सरकार का सार्वजनिक औचित्य-वक्तव्य पहले ही दर्ज है कि लक्ष्य 'लोकनीति में नैतिक मानक उठाना' है न कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी को निशाना बनाना।

लोकतांत्रिक गणराज्य में 'पब्लिक ऑफिस' निजी अधिकार नहीं, सार्वजनिक ट्रस्ट है। रिपब्लिकन एथिक्स कहता है कि किसी भी संभावित 'डॉमिनेशन' चाहे वह शक्ति के भय का या दबाव का हो, से नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जाए। जब कोई मंत्री न्यायिक नियंत्रण में हो तो उसी पद की संस्थागत शक्ति जांच और गवाही को प्रभावित कर सकती है भले ही व्यक्ति दोषी न हो। इस जोखिम से बचाव के लिए 'ऑफिस से अस्थायी दूरी' एक न्यायसंगत व कम से कम हस्तक्षेप वाला उपाय है। पॉपुलिस्ट तर्क, 'जनादेश मिला है, इसलिए पद नहीं छोड़ेंगे' लोकतांत्रिक भावनाओं को भले लुभाए पर संस्थानों की निष्पक्षता और शासन की विश्वसनीयता इसी तरह के स्पष्ट नियमों से ही बची रहती है। नया बिल जनादेश का अनादर नहीं करता वह जनादेश के विश्वसनीय क्रियान्वयन का औजार बनता है।

130वां संशोधन विधेयक और उससे जुड़े पूरक बिल भारतीय लोकतंत्र को एक स्पष्ट संदेश देते हैं। शासन का अधिकार केवल चुनाव जीतने से नहीं बल्कि नियम-आधारित नैतिक उत्तरदायित्व निभाने से भी आता है। 30 दिन, पांच वर्ष, पुनर्नियुक्ति जैसी तराजू से यह ढांचा कठोरता और न्यायसंगतता का संतुलन बनाता है। संयुक्त समिति की जांच, संभव संशोधनों और संसद की बहस के बाद जब यह कानून रूप लेगा तो 'जेल से शासन' के युग का अंत और 'नैतिक वैधता' के नए मानक की शुरुआत दोनों एक साथ दिखेंगे। यही लोकतांत्रिक परिपक्वता है, यही संवैधानिक निष्ठा।

आम जीवन सरल बनाने में मदद कीजिए

केंद्र सरकार / रिजर्व बैंक को आदेश करना चाहिए कि बैंक अपने यहां अतिरिक्त स्टाफ रखे। उसके कार्य सिर्फ खाते धारकों से समय लेकर उनके खातों की केवाईसे कराना हो। सरकार जिस तरह वोट बनवाती है। वोटर का वेरिफिकेशन कराती है। उसी तरह से केवाईसी कराई जाए। इसके बैंक खाता धारकों को सुविधा होगी। केवाईसी कराने के लिए रखे जाने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही काम राज्य की बिजली कंपनी कर सकती हैं। विभागीय मीटर रीडर माह में एक बार रीडिंग लेने उपभोक्ता के घर जाते हैं। वे ही उपभोक्ता से केवाईसी के पेपर लेले। मीटर रीडर को उपभोक्ता जानते हैं उन्हें पेपर देते किसी उपभोक्ता को परेशानी भी नहीं होगी। मीटर रीडर आफिस आकर इस कार्य में लगे स्टाफ को पेपर देकर केवाईसी कराए।

अशोक मधुप

सरकारों का काम आदमी के जीवन को सरल बनाना है। तकनीक के माध्यम से उसे ऐसी सुविधाएं देना है कि वह परेशान न हो, किंतु भारत में हो इसके विपरीत रहा है। उन्हें अलग-अलग काम के लिए थोड़ी- थोड़ी बात के लिए परेशान किया जा रहा है। उनके जीवन को दुरूह किया जा रहा है। आज सबसे बड़ी परेशानी हैं बैंको में जाकर खाते की केवाईसी कराने की। बैंकों की केवाईसी के नाम पर बैंक खाताधारक को परेशान किया जा रहा है। हालत यह है कि केवाईसी करानी है, इसकी उसे सूचना भी नहीं मिलती। उसे उसके लिए बैंक की ओर से मैसेज भी नहीं आता।

मेल आनी चाहिए। किंतु ऐसा हो नहीं रहा। वैसे प्रत्येक ट्रांजेक्शन के मैसेज आते रहते हैं। केबाईसी कराना है, इसका पता तब चलता है जब खातेधारक के चैक का भुगतान रोक दिया जाता है। वह पेमेंट नहीं कर पाता। भुगतान रोकने के कारण चैक जारी करने वाले पर संबधित बैक या सस्थाएं चार सौ से आठ सौ रूपये तक का जुर्माना लगा देती है। मैंने पिछले साल ओरियंटल इंशोरेंस कंपनी को अपनी मेडिक्लेम पोलिसी के लिए चैक दिया। चैक बैंक गया तो भुगतान रूक गया। मैं बैंक गया। बैंक प्रबंधक ने खाता देखकर कहा कि खाता आपका जारी है। चैक का भुगतान कैसे रूका पता नहीं। उनके एक स्टाफ ने देखकर बताया कि खाता बंद किया हुआ है। बैंक प्रबंधक ने कहा कि अब सब कंप्यूटराइज है। हमें पता नहीं चलता और खुद जाता है। बैंक स्टाफ के पता है या नहीं। इससे खाताधारक को क्या लेना। मेरे से तो इंश्योरेंस कंपनी ने चैक डिस ओनर होने के छह सौ रूपये अतिरिक्त वसूल लिए। मुझे तो फालतू का छह सौ रूपये का दंड़ पड़ गया।

अभी लाकर आपरेट करने बैंक जाना पड़ा तो बैंक स्टाफ ने कहा कि इसकी केवाईसी कराइये। हमने कहा कि अभी खाते की तो कराई है। उनका कहना था कि बैंक लॉकर की भी करानी है। लॉकर बैंक के खाते से जुड़ा है, यह बताने पर भी बैंक कर्मी नहीं माने। यदि आपके पास चार-पांच बैंक खाते हैं तो प्रत्येक दो साल से केवाईसी कराने जरूर जाना होगा।

अभी तक बैंक खाते चालू रखने के लिए केवाईसी करानी थी। अब बिजली विभाग के मैसेज आ रहे हैं, कि अपने कनेक्शन की ईकेवाईसी कराइए। आज जहां चारों ओर धोखे का जाल फैला है। ठग आपको फंसाने में लगे हैं, ऐसे में किस मैसेज को सही माना जाए, किसे गलत यह कैसे पता चले। अभी परिवहन विभाग का मैसेज आया है कि आधार आथोराइजेशन माध्यम से अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराइए। समझ नही आ रहा कि क्या-क्या कराएं। हम पर ये सब करना नहीं आता। इसका मतलब ये की रोज जनसेवा केंद्र पर जाइये। लाइन में लगिए और पैसा भी दीजिए। लगता है कि कहीं ये जनसेवा केंद्र की आय बढ़ाने के लिए तो नहीं किया जा रहा।

अभी पिछले दिनों आदेश आया कि अपना आधार कार्ड प्रत्येक दस साल में अपडेट कराना है। मैं छोटे शहर में रहता हूं। यहां कि आबादी दो लाख के करीब है। पूरे शहर में आधार कार्ड अपडेट कराने का एक ही सेंटर है। मुख्य डाकघर। उसमें आधार कार्ड बनवाने वालों की सवेरे आठ बजे से लाइन लग जाती है। हम 75 साल से ऊपर के पति-पत्नी कैसे उस लाइन में लगें, ये कोई सोचने और बताने वाला नहीं है। दूसरे केंद्र का दरवाजा खुलने पर इस तरह धक्का-मुक्की होती है कि हम लाइन में लगे तो हाथ-पांव तुड़ाकर जरूर अस्पताल जाएंगे।

केंद्र सरकार / रिजर्व बैंक को आदेश करना चाहिए कि बैंक अपने यहां अतिरिक्त स्टाफ रखे। उसके कार्य सिर्फ खाते धारकों से समय लेकर उनके खातों की केवाईसे कराना हो। सरकार जिस तरह वोट बनवाती है। वोटर का वेरिफिकेशन कराती है। उसी तरह से केवाईसी कराई जाए। इसके बैंक खाता धारकों को सुविधा होगी। केवाईसी कराने के लिए रखे जाने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही काम राज्य की बिजली कंपनी कर सकती हैं। विभागीय मीटर रीडर माह में एक बार रीडिंग लेने उपभोक्ता के घर जाते हैं। वे ही उपभोक्ता से केवाईसी के पेपर लेले। मीटर रीडर को उपभोक्ता जानते हैं उन्हें पेपर देते किसी उपभोक्ता को परेशानी भी नहीं होगी। मीटर रीडर आफिस आकर इस कार्य में लगे स्टाफ को पेपर देकर केवाईसी कराए। हो यह रहा है कि संबधित विभाग बैंक/ बिजली अपना कार्य उपभोक्ता पर डाल उसके जीवन को कठिन बना रहे हैं, जबकि उन्हे अपने ग्राहकों को सुविधाएं देनी चाहिए थीं। ऐसा ही आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। हां इसके लिए उपभोक्ता से थोड़ा बहुत चार्ज लिया जा सकता है। अभी एक मैसेज आया कि आपका इन्कमटैक्स का रिटर्न स्वीकार कर लिया गया है। मैंने अभी रिटर्न भरा नहीं, सो ये मैसेज बेटे को भेज दिया कि शायद उसने रिटर्न भरा हो। उसका जबाब आया कि पापा इस मैसेज के लिंक पर क्लिक मत करना। ये गलत लगता है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि सही और गलत का कैसे तय हो। किसी न किसी तरह धोखे में लेकर रोज हजारों व्यक्ति रोज ठगे जा रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए? ऐसे हालात में जीवन दुरूह होता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों को आम आदमी का जीवन को सरल बनाने के लिए काम करना चाहिए।

IIT Council Agrees to Accreditation, Framework Yet to be Finalised

New Delhi. The Indian Institutes of Technology (IITs) will now move towards a formal system of accreditation, a step agreed upon during the meeting of the IIT Council — the apex coordination body of the premier institutions — held on Monday. However, questions remain over which agency will accredit them and what the detailed framework will look like, a senior Ministry of Education official confirmed. The National Education Policy (NEP) 2020 had recommended the establishment of a National Accreditation Council (NAC), envisioned as an overarching body for accrediting higher education institutions under the proposed Higher Education Commission of India (HECI). However, this larger reform is still pending. Currently, the IITs do not fall under the ambit of the National Assessment and Accreditation Council (NAAC), which evaluates most Indian higher education institutions. Instead, they follow an internal system of peer review and periodic assessment of programmes. A 2023 committee report, chaired by Dr. K. Radhakrishnan, had recommended bringing IITs under a unified accreditation process to ensure transparency and uniform standards. The council also discussed non-academic issues, particularly student mental well-being. Officials said IIT Madras presented details of initiatives it has taken in this area. The meeting further emphasized overcoming language barriers in education. Union Education Minister Dharmendra Pradhan urged IITs to incorporate regional languages in their instruction to ensure inclusive growth. Decisions on this front, however, will be left to the Senate of each IIT. At present, IIT Jodhpur is the only institution offering the option of first-year BTech classes in Hindi.

Another agenda item — the implementation of the National Credit Framework — was not taken up for discussion, though officials said the IITs have already developed a framework for it. The meeting was significant as it came after a gap of two years, the last one being held in April 2023.

Commonwealth Shared Scholarships Open for Applications

The Commonwealth Shared Scholarships programme, offered in partnership with participating UK universities, is now open for applications. These scholarships are aimed at candidates from low- and middle-income Commonwealth countries who would otherwise be unable to study in the UK due to financial constraints. Applicants must not have studied or worked in a high-income country for more than one academic year. They are also required to provide proof of financial need, along with all necessary supporting documents in the prescribed format. The scholarships cover a one-year full-time Master's degree in eligible courses and include tuition fees, return airfare, and a living allowance. Applications must be submitted through participating UK universities, which conduct the initial round of selection. The final approval is made by the Commonwealth Scholarship Commission (CSC), ensuring that chosen scholars align with the programme's development-oriented objectives. The award is strictly limited to the approved course and cannot be extended for further studies or additional qualifications. Recipients are also not permitted to enroll in any other academic programme during the scholarship tenure, as stated on the official CSC website.

Major relief for medical students in Madhya Pradesh as MBBS admission deadline extended till August 28, two new colleges add 200 seats

Bhopal. A big relief has come for medical aspirants in Madhya Pradesh. The state government has announced that the admission deadline for MBBS courses has now been extended till August 28. This means that students who were unable to complete their admission process earlier will now get additional time to apply. The decision comes in the wake of two new medical colleges being established in the state, which together have added 200 new MBBS seats. Currently, Madhya Pradesh has a total of 32 functional medical colleges. Until recently, there were 17 government medical colleges, but with the addition of two new institutions, the number has increased to 19. Alongside these, the state also has 13 private medical colleges, while six more medical colleges are under construction. Officials believe this expansion will not only provide more opportunities for aspiring doctors but will also significantly strengthen healthcare services across the state. The expansion of medical education infrastructure has long been considered necessary in Madhya Pradesh. With the addition of new colleges, students will have reduced need to move outside the state for medical studies, as they will now have access to quality medical education locally. Moreover, an increase in the number of medical professionals is expected to enhance the reach of healthcare services in both rural and urban areas. Experts have welcomed this move, calling it a major step towards transforming Madhya Pradesh into a hub for medical education in the future. They also pointed out that the increased number of seats will ease the competitive pressure among students to some extent, ensuring that talented and deserving candidates get better opportunities to pursue their dreams of becoming doctors.

Education Minister Calls For IITs To Lead 'Atmanirbhar Bharat' Vision

Union Education Minister Dharmendra Pradhan on Monday chaired the 56th meeting of the Council of Indian Institutes of Technology (IITs) at IIT Delhi. The Council resolved to advance the Prime Minister's vision of "Atmanirbharta se Samridha Bharat" and strengthen IITs as drivers of self-reliance, innovation, and inclusive growth.

Addressing the meeting, Mr Pradhan said IITs must position themselves as catalysts for an Atmanirbhar and Samriddha Bharat. He stressed that India was not aiming for incremental change but for a "quantum jump" and urged the premier institutes to take the lead. Emphasising inclusive education, he called for the introduction of regional languages in addition to English as mediums of instruction. He also underlined the need for IITs to focus on producing job creators by solving real-world problems and strengthening translational research in critical national technologies.

Highlighting IITs' role in entrepreneurship and innovation, Mr Pradhan said the institutes had already nurtured over 6,000 start-ups, 56 unicorns, and nearly 5,000 patents. "Confident that our IITs will translate national aspirations into outcomes, create large-scale employment and economic opportunities, contribute significantly to fulfil the vision of Samridhh and Viksit Bharat by 2047 and also emerge as engines of India's civilisational resurgence and global leadership," he said in a post on X. Supported by initiatives such as the PM Research Fellowship, Centres of Excellence in AI, and research parks, IITs, he said, were emerging as engines of economic growth in line with the Prime Minister's call to "Reform, Perform, Transform."

Minister of State for Education and DoNER, Dr Sukanta Majumdar, said IITs were not just centres of learning but engines of Innovation, Inclusion, and Transformation driving India's journey towards Viksit Bharat 2047. He noted that with 23 IITs, international campuses, and a vibrant startup ecosystem, IITs were producing global leaders and innovators while ensuring India continues to RISE through Research, Innovation, Skills, and Entrepreneurship.

SSC Overhauls Exam System With Aadhaar, 59,000 Candidates To Reappear After Glitches

The Staff Selection Commission (SSC) has revamped its system of conducting Computer-Based Tests (CBTs) by introducing Aadhaar-based authentication, a new normalisation method and tighter monitoring of private centres, to curb malpractices that have long plagued recruitment tests. A log analysis has also identified about 59,000 affected candidates for whom a re-exam is scheduled on August 29, in three exam shifts to ensure fairness. This at the backdrop of massive protests by aspirants on Sunday night, where more than a thousand aspirants and teachers gathered at the Ramlila Maidan in the capital. Over 40 protesters were detained by the police. Last month, a similar protest was held at Jantar Mantar. Till June 2025, Tata Consultancy Services (TCS) had been the exam conducting agency (ECA) for SSC. From July 2025, Eduquity Career Technologies took charge, as mandated by an open tender. In a major change following a Supreme Court order, the task of setting questions has been separated from the ECA and handed over to independent content agencies.

What are the New Safeguards?

One of the most significant reforms introduced from July 2025 is Aadhaar-based authentication at both registration and exam venues. SSC Chairman, S Gopalakrishnan said that this has sharply reduced impersonation-a rampant problem in SSC exams. "We discovered earlier that one person had written the exam ten times. That is now impossible. Aadhaar also simplifies the application process and benefits both SSC and candidates," the chairman explained. CDAC has also been roped in for IT security, with technical integration between CDAC and Eduquity being rolled out, though not without initial glitches.

Digital Question Delivery has also been implemented. Questions are now delivered digitally from multiple content agencies, reducing over-reliance on one vendor. Four different agencies are currently involved in conducting SSC exams, each with distinct roles. The Commission has also decided to provide different question sets in each shift to prevent candidates from gaining an unfair advantage by accessing memory-based questions shared on social media. "Earlier, one entity would set the question paper and conduct the exam. This led to malpractice and impersonation. We have now separated these roles so that every candidate can write the exam only once," the chairman said.

Centres and Candidate Concerns

Candidates have also raised concerns over exam centres, with some initially allotted far-off cities due to fewer centres compared to TCS. Mr. Gopalakrishnan clarifies that this has since been rectified, citing "the stenographer exam, in which 80 per cent of candidates got their preferred centres. Data has been published on the website for transparency. We will continue this in future." One of the biggest changes is in the way multi-shift exams are evaluated. The chairman highlighted that lakhs of candidates appear for SSC exams, so they are conducted in multiple shifts. "If one paper is easier than another, candidates suffer. We have now changed the normalisation formula so that marks are awarded based on the relative difficulty of each shift. This ensures fairness," he said.

On complaints about malpractices at private exam centres, the chairman mentioned that the commission has integrated a CDAC monitoring solution with its exam software and allows real-time oversight of all machines and test locations. Admitting to the exam disruptions in the very first round of exams held in July between July 24 and August 2, the chairman said, "yes, exams stopped midway at some centres, but the issue was fixed during the same test. The system has now stabilised" adding that the CGL exam was deferred slightly to ensure smooth conduct. Around 5.5 lakh candidates had appeared for these exams. On July 24, exams had to be cancelled at two venues due to system issues. Candidates also reported problems like system hang-ups, biometric mismatches, and time shortages.

Coaching Institutes Push Back

Meanwhile, coaching institutes have been at the forefront of protests against the new system, demanding a return to TCS. SSC insiders allege this resistance is motivated, as Aadhaar-based checks and a shift in question patterns have undercut their traditional preparation models. According to SSC officials, "E-dossiers have eliminated fake submissions, Aadhaar-based authentication has curbed impersonation at two levels, and changes in question patterns have made older study material less useful - directly affecting coaching businesses."

What is the Road Ahead?

The flagship Combined Graduate Level (CGL) exam, originally slated for August 13, has been rescheduled to mid-September to allow more time for operational stability. Officials maintain that, with multiple agencies now handling different aspects of exams-from question-setting to IT security and monitoring-the system will emerge more resilient. While teething troubles remain, SSC maintains that the current disruptions are transitional. With multiple agencies now engaged, from content providers to IT security and monitoring, the system, officials guarantee will be more robust and transparent in the long run. The Staff Selection Commission (SSC) is a central government body that conducts competitive exams to recruit staff for various Group B (non-gazetted) and Group C (non-technical) posts in ministries, departments, and other government offices.

CBSE, AIIMS Delhi begin five-day counsellor training for student well-being

The Central Board of Secondary Education (CBSE) has teamed up with the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Delhi, to launch a wellness initiative aimed at strengthening the role of school counsellors in supporting students.

Called Project MATE (Mind Activation Through Education), the programme began on August 26 at AIIMS Delhi and will run until August 30. It brings together around 50 counsellors and wellness teachers from CBSE-affiliated schools across the Delhi-NCR region for an intensive five-day training. Developed by experts at AIIMS, Project MATE follows the "MATE-5" framework, which is designed to help adolescents build resilience, cope with stress, and foster stronger peer connections. The sessions cover topics ranging from the biopsychosocial model of health, nutrition, and family dynamics, to managing anxiety, promoting digital well-being, and effective counselling strategies. Specialists in psychiatry, psychology, and communication are facilitating the training. The programme also includes modules on parental awareness, tools for measuring the impact of interventions, and creating peer-led support systems. According to officials, the goal is to give counsellors a structured toolkit to address issues such as loneliness, emotional disconnection, and conflict amongst students.

At the launch, CBSE and AIIMS representatives underlined the importance of integrating education and health to safeguard adolescent well-being. They stressed that mental health must be treated as a core part of holistic education rather than an afterthought. This initiative is being rolled out as a pilot project, with CBSE planning to monitor outcomes closely. Depending on the results, Project MATE could be scaled up to a national level. Officials expect it to strengthen the school counselling ecosystem, encourage early interventions for mental health challenges, and help normalise conversations around emotional well-being amongst young people.

No more work in office, 51% of employees believe AI could replace physical offices

Physical offices may soon lose their relevance, and employees are likely to have more remote jobs. A new GoTo study, The Pulse of Work in 2025: Trends, Truths, and the Practicality of AI, shows that 51% of employees believe artificial intelligence could eventually eliminate the need for traditional workplaces. The global survey, conducted with Workplace Intelligence, gathered insights from 2,500 employees and IT leaders across multiple regions. The study covered workers in the US, Canada, Europe, India, and Latin America, with an equal mix of remote, hybrid, and in-office respondents.

AI AS A WORKPLACE EQUALISER

One of the key takeaways of the survey is that more than half of employees (51%) believe AI could eventually render physical offices unnecessary. In the survey, it was a big finding that not all jobs can be done remotely. The survey also reflects 62% of workers still prefer AI-enabled remote work over being in the office. The research indicates strong support for AI investments across various fields. Nearly all employees (95%) and IT leaders (92%) either back current spending on AI tools or believe companies should invest more in training programmes, in equipping employees with AI tools. Benefits cited include better work-life balance (71%), higher flexibility (66%), and improved customer service while working remotely (65%).

IT leaders appear more optimistic than workers about the impact of AI. Nine in ten IT leaders say AI tools are being used effectively to support remote and hybrid teams, but only 53% of employees agree. The gap underscores a disconnect companies may need to address. Generational differences are less stark than expected. Productivity gains from AI were reported across all age groups: Gen Z (90%), Millennials (84%), Gen X (71%), and Baby Boomers (74%). This suggests AI adoption is not limited to younger workers but is becoming a cross-generational tool.

SHIFTING PRIORITIES AT WORK

Another finding concerns the trade-off between office perks and digital tools. About 61% of employees say companies should prioritise AI investments at least as much as, if not more than, workplace amenities.

Rich Veldran, CEO of GoTo, said AI is no longer just a support mechanism but a core driver of workplace change. "The companies that embrace AI not just as a tool, but as a core part of their employee experience, will be the ones that redefine what it means to be productive, connected, and collaborative wherever work happens," he said.

Dan Schawbel, managing partner at Workplace Intelligence, noted that flexibility, not location, is becoming the anchor of modern work. "AI helps bridge time zones, streamline communication, and provide access to knowledge, making physical offices feel less critical," he said.

Even those working primarily on-site expressed a preference for AI tools over traditional office benefits. In 2025 and in the upcoming years, it is evident that workplaces and ways of work will see more shifts, AI will play a major role and the way in which so far organisations have worked may tend to change.

27 अगस्त को गणेश चतुर्थी, स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त

वैसे तो रोजाना ही भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है, लेकिन भादों माह प्रभु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, जिसकी खुशी में देशभर में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दौरान भक्तजन घरों, दफ्तरों, दुकानों और मंदिरों में गणपति जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधिनुसार उपासना करते हैं। इसके अलावा प्रभु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए मोदक, मोतीचूर लड्डू, खीर और मालपुआ जैस भोग लगाए जाते हैं, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। इस वर्ष 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। इस दिन गणपति जी की मूर्ति की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए विस्तार से जानते हैं।

गणेश चतुर्थी तिथि 2025

इस बार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर होगा। इसका समापन 27 अगस्त की दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर हो रहा है। उदया तिथि के मुताबिक गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा।

स्थापना मुहूर्त

ज्योतिषियों के मुताबिक गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के लिए 27 अगस्त को सुबह 11 बजकर 05 मिनट से लेकर दोपहर 01 बजकर 40 मिनट तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप इस अवधि में गणपति जी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं।

गणेश चतुर्थी दुर्लभ संयोग

इस बार गणेश चतुर्थी पर प्रीति, सर्वार्थ सिद्धि, रवि के साथ इंद्र-ब्रह्म योग का संयोग बना रहेगा। वहीं कर्क में बुध और शुक्र के होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर बुधवार का महासंयोग तिथि की महत्ता को गई गुना बढ़ा रहा है।

गणेश चतुर्थी पंचांग 2025

सूर्योदय सुबह 05 बजकर 57 मिनट पर
सूर्यास्त शाम 06 बजकर 48 मिनट पर
चंद्रोदय सुबह 09 बजकर 28 मिनट पर
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 28 मिनट से 05 बजकर 12 मिनट तक
विजय मुहूर्त दोपहर 02 बजकर 31 मिनट से 03 बजकर 22 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त शाम 06 बजकर 48 मिनट से 07 बजकर 10 मिनट तक
इस दिन निशिता मुहूर्त रात 12 बजे 12 बजकर 45 मिनट तक

इन उपायों से प्रसन्न होते है विघ्नहर्ता गणेश जी, पूरी करते हैं सभी मनोकामना

हिंदू संस्कृति और किसी भी तरह की पूजा में भगवान श्रीगणेश जी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। किसी भी शुभ काम या पूजा को शुरू करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। देवता भी अपने कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूरा करने के लिए गणेश जी की अर्चना सबसे पहले करते हैं। मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा न केवल आपके कार्यों में आ रही अड़चनों को हटाती है, बल्कि आपकी हर मनोकामना को भी पूरी करती है।

हम सभी के मन में कई सारी इच्छाएं होती हैं। इनमें से कुछ पूरी हो जाती हैं जबकि कुछ अधूरी ही रह जाती हैं। ऐसे में अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए आप गणेशजी के चरणों में जा सकती हैं। जी हां विघ्नहर्ता गणेशजी को हमारे भाग्य विधाता भी हैं। इसलिए अगर आपकी खोई ख्वाहिश अधूरी है और उसे पूरा करना चाहती हैं तो गणेशजी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए गणेश जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। आइए आप भी हमारे साथ विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रसन्न करने के टिप्स के बारे में जानें।

दूर्वा

गणेश जी को खुश करने का सबसे सस्ता और आसान उपाय दूर्वा अर्पित करना है। दूर्वा गणेश जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि दूर्वा में अमृत मौजूद होता है। गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा दुर्वांकुर से करता है वो कुबेर के समान हो जाता है। गणेश जी को कम से कम 21 दूब, 2 शमी और 2 बेल पत्र चढ़ाया जाता है। तुलसी जी गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती हैं।

मां बाप की सेवा

विघ्नहर्ता गणेश जी को खुश करने का सबसे अच्छा रास्ता मां-बाप की सेवा करना है। गणेश जी उसे ही अपनी भक्ति प्रदान करते हैं जो अपने माता-पिताजी और सास-ससुरजी की सेवा करता है। बुजुर्गों का सम्मान करता है। तीर्थयात्रा आदि हेल्दी रहने पर माता-पिताजी और सास-ससुर जी के साथ ही करता है। इसके अलावा वृक्ष लगाने वालों से भी गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अपने जीवनकाल में कम से कम 108 वृक्ष लगाएं और उन्हें संतान की तरह पाले, बड़ा करें। गणेश जी इन कार्यो से अति प्रसन्न होंगे।

लड्डू

गणपति बप्पा को लड्डू खाना बड़ा पसंद हैं। ये उनके प्रिय व्यंजनों में से एक हैं। अगर आपके मन में कोई भी ख्वाहिश हैं तो आप गणेश मंदिर जाकर विघ्नहर्ता को लड्डुओं को भोग लगा सकते हैं। मूंग की दाल के लडडू गणेश जी को बहुत प्रिय होते हैं। घर में ही पूजा करें तो पूजा के पूरा होने के बाद 21 में से 15 लडडू पंडित जी को दक्षिणा सहित दान कर दें। दक्षिणा नहीं दी तो श्री कथावाचक और श्री ज्योतिषी को ही आपका पुण्य प्राप्त हो जाएगा। गर्मियों में गणेश जी को मूंग के दाल के लड्डू और सर्दियों में गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए।

जल अर्पित करना

सुबह गणेश जी के 12 नाम जपते हुए ही उठें। जो नासिका चल रही हो वही पैर गणेश जी कहते हुए रखें। नहाने के बाद सबसे पहले गणेश जी को जल उत्तर दिशा में अर्पित करें। जल को जल में ही अर्पित करना है। यानि आप जिस जगह जल चढ़ाएं वहां या तो कोई गमला रख दें या पहले से ही पानी को गिरा दें। इसके बाद ही पूर्व में सूर्य नारायण और दक्षिण दिशा में अपने पितरों को जल अर्पित करें।

फल

अगर आपके पास धन है तो रोज गणेश जी को कोई न कोई फल जरूर खिलाएं। और पूजा करके इसे तुरंत खा जाये, इसे खाना नहीं है। जामुन, अमरूद, बेल, आम, सेब, संतरा, मौसमी, चीकू, केला, अनार, आलुबुखारा, नारियल आदि मौसम के अनुसार फलों का भोग गणेश जी को लगाना चाहिए।

गणेश चतुर्थी के दिन कौन सा दीया जलाना होता है ज्यादा शुभ?

भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की घर में स्थापना कर उनकी पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन पूजा के दौरान गणेश जी के समक्ष कौन सा दीया जलाना चाहिए और क्या हैं उससे मिलने वाले लाभ।

गणेश जी के सामने अलसी के तेल का दीया जलाना शुभ माना जाता है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन भी गणपति स्थापना के बाद उनके सामने अलसी के तेल का दीया प्रज्वलित करें। अलसी के तेल का संबंध मां लक्ष्मी से होता है। अलसी के तेल से किये गए उपाय धन को आकर्षित करने का काम करते हैं। गणेश जी के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इसमें अगर गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के बाद उनके सामने अलसी के तेल का दीया जलाया जाए तो गणेश जी घर में अपनी कृपा के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आते हैं। इसके अलावा, अलसी के तेल का दीया गणेश जी के सामने जलाने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में मौजूद कैसा भी ग्रह या वास्तु दोष दूर होने लग जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन अलसी के तेल में अगर कलावे की बत्ती डालकर दीया जलाया जाए तो इससे घर में शुभता आती है औरशुभ कामों में आ रही बाधाएं भी दूर होने लग जाती हैं।

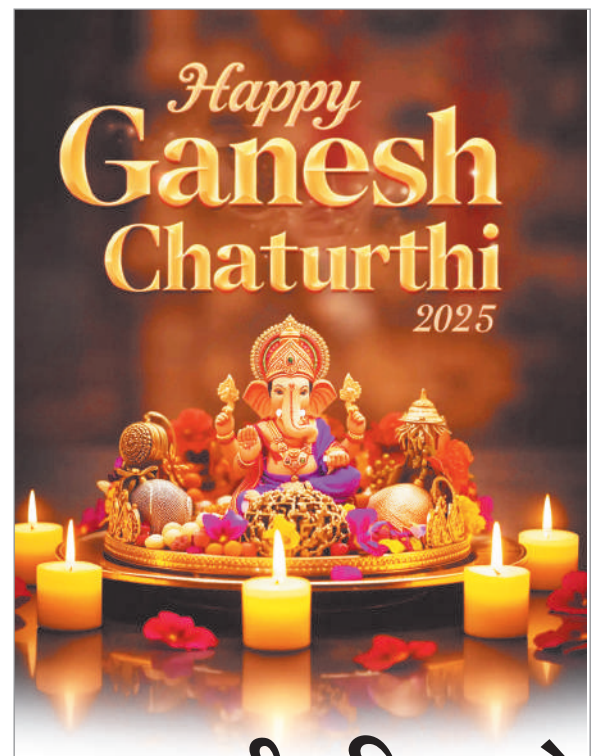

बप्पा की प्रतिमा को घर लाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बप्पा की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि पूजा से पहले किन नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है।

गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि वे सभी शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले पूजे जाने वाले पहले देवता हैं। गणेश जी को सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले देवता माना जाता है। इसलिए, किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाती है। आपको बता दें, गणेश चतुर्थी को नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग नए काम शुरू करते हैं और नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। गणेश जी को सुख-समृद्धि के देवता भी माना जाता है। इसलिए, इस दिन लोग उनके आशीर्वाद के लिए पूजा करते हैं। अब ऐसे में अगर आप बप्पा को घर लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो किन नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है।

दिशा का रखें विशेष ध्यान

भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने से पहले दिशा के बारे में जानने बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए अगर आप बप्पा की प्रतिमा को स्थापित करने का सोच रहे हैं, तो हमेशा ईशान कोण दिशा का ही चुनाव करें। साथ ही बप्पा का मुख हमेशा उत्तम दिशा की ओर होना चाहिए। इसके अलावा आप पश्चिम दिशा में बप्पा की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं।

बप्पा की प्रतिमा का करें सही चुनाव

वास्तु शास्त्र में बप्पा की प्रतिमा को बिना मूषक के न स्थापित करें। गणेश जी की प्रतिमा लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके हाथों में मोचक और मूषक का होना बेहद महत्वपूर्ण है। बिना मूषक के पूजा अधूरी मानी जाती है।

बप्पा की प्रतिमा का रंग हो सही

अपनी इच्छा के अनुसार घर में आप बप्पा की किसी भी रंग की प्रतिमा लेकर आ सकत हैं। विशेष रूप से सफेद और सिंदूरी रंग की प्रतिमा घर में लाना सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसी प्रतिमा को घर में स्थापित करने से सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है।

गणेश चतुर्थी का महत्व

हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन दोपहर के समय हुआ था, इसीलिए इस तिथि और समय को अत्यंत शुभ माना जाता है। वे प्रथम पूज्य, बुद्धि के दाता और विघ्नों को हरने वाले देवता हैं। कोई भी धार्मिक कार्य, विवाह, यात्रा या नया कार्य बिना गणपति पूजन के शुरू नहीं किया जाता। इस दिन का भक्तों को सालभर इंतज़ार रहता है क्योंकि यह दिन उनके लिए उत्सव, भक्ति और आनंद से भरा होता है।

गणेश चतुर्थी से पहले जरूर खरीदें ये चीजें, मिलेंगे शुभ परिणाम

हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। गणेश चतुर्थी को गणेशोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बप्पा की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। बता दें, इस साल गणेश उत्सव 27 अगस्त को मनाया जाएगा। भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता माना गया है। सभी देवी-देवताओं से पहले बप्पा की पूजा करने का विधान है। अब ऐसे में गणेश चतुर्थी से पहले किन चीजों का खरीदना शुभ माना जाता है। इसके बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी से विस्तार से जानते हैं। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान शंख बजाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-समृद्धि लाते हैं। शंख को वास्तु दोष निवारण का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। इसे घर में सही दिशा में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वहीं गणेष चतुर्थी से पहले शंख को खरीदने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी से पहले घर लाएं हरे वस्त्र हरा रंग प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान गणेश को हरा रंग बहुत प्रिय है। इसलिए, गणेश चतुर्थी के दौरान हरे रंग के वस्त्र पहनकर या गणेश जी को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गणेश चतुर्थी से पहले हरे रंग का वस्त्र अवश्य खरीदें।

गणेश चतुर्थी से पहले घर लाएं चांदी का कलश

चांदी को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी को धन के देवता भी माना जाता है, इसलिए चांदी का कलश लाकर घर में धन की वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, आप इस दिन चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं। इससे व्यक्ति को उत्तम परिणाम मिल सकते हैं।

गणेश चतुर्थी से पहले घर लाएं इलायची

इलायची को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इलायची को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की शक्ति मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी को इलायची बहुत पसंद है। इसलिए, इलायची को गणेश जी को अर्पित किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन एक लाल कपड़े में 5 इलायची बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रखें, इससे धन में वृद्धि होती है।

जानिए आखिर क्यों भगवान गणेश की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए

ऐसा माना जाता है कि गणेश जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते है और अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। अगर कोई भक्त गणेश जी की पूजा अर्चना की जाए तो उनके सभी दुख भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कभी भी भगवान गणेश की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है।

गणेशजी को रिद्धि-सिद्धि का दाता माना गया है और इनकी पीठ के दर्शन करना वर्जित किया गया है। मान्यताओं के अनुसार, गणेश जी के शरीर पर जीवन और ब्रह्मांड से जुड़े अंग निवास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार, गणेश जी के शरीर के हर अंग पर ब्रह्मांड की क्रियाएं छिपी हुई होती हैं। गणेश जी के कानों पर ऋचाएं, सूंड पर धर्म विद्यमान, दाएं हाथ में वर, बाएं हाथ में अन्न, पेट में समृद्धि, आंखों में लक्ष्य, नाभि में ब्रह्मांड, पैरों में सातों लोक और मस्तक में ब्रह्मलोक विद्यमान है। गणेशजी के सामने से दर्शन करने पर उपरोक्त सभी सुख-शांति और समृद्धि प्राप्त हो जाती है लेकिन माना जाता है श्रीगणेश की पीठ पर दरिद्रता का निवास होता है। गणेशजी की पीठ के दर्शन करने वाला इंसान अगर बहुत धनवान भी हो तो उसके घर पर दरिद्रता का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी कारण इनकी पीठ नहीं देखना चाहिए।

भगवान गणेश की पीठ का दर्शन कर ले तो क्या करना चाहिए?

अगर आपने भगवान गणेश की पीठ के दर्शन कर लिए हैं तो श्री गणेश से क्षमा याचना मांग लेना चाहिए। ऐसा करने से इसका प्रभाव खत्म हो जाए। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार, अगर आपका कोई भी काम रुक रहा हो या फिर आप कोई भी काम करने में असमर्थ हो तो भगवान गणेश का मात्र नाम लेने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।

सचिन तेंदुलकर ने बेटे की सगाई की पुष्टि की

फैंस के सवाल पर कहा- हां, यह सच है, अपनी पसंदीदा पारी पर भी बात की

मुंबई (एजेंसी)। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई की पुष्टि की है। तेंदुलकर ने एक फैंस के सवाल पर कहा- हां, यह सच है। हम सभी उनके जीवन के इस नए फेज के लिए बहुत उत्साहित हैं। 52 साल के पूर्व क्रिकेटर ने सोमवार को सोशल प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक सेशन 'आस्क मी एनीथिंग' के जरिए फैंस के सवालों के जवाब दिए। 13 अगस्त को मीडिया रिपोर्ट में अर्जुन तेंदुलकर की सगाई का दावा किया गया था, हालांकि तब किसी ने सगाई की पुष्टि नहीं की थी।

फैंस के सवाल पर तेंदुलकर के जवाब

सवाल-1 -2011 वर्ल्ड कप फाइनल में धोनी को युवराज से पहले भेजने का सुझाव क्यों दिया?

जवाब -तेंदुलकर ने इसके पीछे 2 वजहें बताईं... लेफ्टी-राइटी बैटिंग कॉम्बिनेशन सचिन ने कहा- लेफ्टी-राइटी बैटिंग कॉम्बिनेशन श्रीलंका के दो ऑफ-स्पिनर्स (मुथैया मुरलीधरन और सूरज रणदीव) के लिए परेशानी खड़ी कर सकता था।

धोनी के पास मुरली को खेलने का अनुभव सचिन ने बताया- मुरलीधरन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए 2008 से 2010 तक खेल चुके थे। धोनी ने नेट्स पर तीन सीजन तक उनकी गेंदबाजी का सामना किया था।

तेंदुलकर की यह सलाह शानदार साबित हुई। धोनी ने फाइनल में नाबाद 91 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत को श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत दिलाई। इस जीत ने भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनाया।

सवाल-2 - कौन-सी पारी सबसे खास रही?

जवाब- सचिन ने कई शानदार पारियों का जिक्र करते हुए 2008 में चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई अपनी नाबाद 103 रनों की पारी को सबसे खास बताया। इस पारी में सचिन ने चौथी पारी में 387 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को छह विकेट से जीत दिलाई थी। यह मैच इंग्लैंड के कप्तान केविन पीटरसन की अगुआई में खेला गया था। भारत ने इस जीत के साथ दो टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम की थी।

सवाल-3 -वेस्टइंडीज या ऑस्ट्रेलिया...किस देश के गेंदबाज बेहतर हैं?

जवाब- सचिन ने इसका जवाब देने की बजाय मजेदार अंदाज में सवाल किया। उन्होंने लिखा- क्यों? क्या आप इनके खिलाफ खेलने की योजना बना रहे हैं? इस पर फैंस ने हंसने के इमोजी पोस्ट किए।

सवाल-4 - ग्लेन मैक्ग्रा के खिलाफ जोखिम भरे शॉट्स क्यों खेले थे?

जवाब -सचिन ने कहा- मैंने कई मौकों पर जोखिम भरे शॉट्स खेले, ताकि गेंदबाज की लय टूटे। मुझे नैरोबी में 2000 में मैक्ग्रा के खिलाफ खेला गया शॉट याद है। सचिन ने उस पारी में 37 बॉल पर 38 रन बनाए थे। उस मैच में मैक्ग्रा ने 9 ओवर में 61 रन दिए थे। उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था।सचिन ने 38 रन की पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए थे। इनमें से 5 बाउंड्री मैक्ग्रा के ओवर में लगाई थीं।

सवाल-5-क्या अर्जुन की सगाई हो चुकी है?

इस पर सचिन ने कहा- हां, यह सच है और हम सभी उनके जीवन के इस नए फेज के लिए बहुत उत्साहित हैं। अर्जुन (25) और सानिया (26) ने 13 अगस्त को एक निजी समारोह में सगाई की, जिसमें केवल करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल थे। सानिया, व्यवसायी रवि घई की पोती हैं। जबकि, अर्जुन गोवा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और आईपीएल में भी नजर आ चुके हैं। अर्जुन ने सोशल मीडिया पर कोई व्यक्तिगत घोषणा नहीं की।

उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 9 अगस्त को थी, जिसमें उन्होंने अपनी बहन सारा तेंदुलकर को रक्षा बंधन की शुभकामनाएं दी थीं। सगाई की खबरों ने ऑनलाइन काफी ध्यान खींचा था, और अब सचिन की पुष्टि के साथ सारी अटकलों पर विराम लग गया है।

दो बार की विम्बलडन चैम्पियन क्वितोवा ने टेनिस को कहा अलविदा

न्यूयॉर्क (एजेंसी)। दो बार की विम्बलडन चैम्पियन पेत्रा क्वितोवा ने अमेरिकी ओपन के पहले दौर में डायने पैरी से मिली हार के बाद टेनिस को अलविदा कह दिया। मुकाबला खत्म होने के बाद क्वितोवा की आंखें भर आई। दर्शक दीर्घा में मौजूद उनके पति और कोच जिरि वानेक ने उन्हें गले लगाया। पिछले साल जुलाई में बेटे को जन्म देने वाली क्वितोवा 17 महीने बाद कोर्ट पर लौटी थी। उन्होंने इस साल की शुरूआत में ही कह दिया था कि अमेरिकी ओपन उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि कुछ सप्ताह पहले वह कोविड 19 संक्रमण का शिकार होने के कारण अमेरिकी ओपन से नाम वापिस लेने की सोच रही थी। उन्होंने कहा, 'सुबह उठने के बाद से मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं खा नहीं सकी। मैं काफी नर्वस थी और कुछ कर नहीं पा रही थी। यह काफी कठिन था। मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। क्वितोवा ने 2011 में मारिया शारापोवा को हराकर विम्बलडन खिताब जीता था। इसके बाद 2014 में यूजीन बूचार्ड को हराकर खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 के फाइनल में उन्हें नाओमी ओसाका ने हराया था। दिसंबर 2016 में उनके घर पर एक घुसपैठिये ने उन पर चाकू से हमला किया जिससे लगी चोट से उबरने के लिये उन्हें लंबी सर्जरी करानी पड़ी थी।

वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की गोल्डन वापसी

● **कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, पेरिस ओलिंपिक के बाद पहला मुकाबला खेल रही थी**

अहमदाबाद (एजेंसी)। भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में चल रही कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। 48केजी वेट कैटेगरी में शिरकत करते हुए चानू ने कुल 193 केजी वेट उठाया। स्नैच में उनकी बेस्ट लिफ्ट 84 केजी की रही, वहीं क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 109 केजी वजन उठाया। चानू पेरिस ओलिंपिक के बाद पहली बार किसी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उतरी थीं। 2020 टोक्यो ओलिंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट चानू पेरिस ओलिंपिक में मेडल जीतने से चूक गईं थीं। तब वे चौथे स्थान पर रही थीं।

स्नैच में 1 प्रयास ही सफल हो पाया – चोट की वजह से चानू करीब 1 साल से इंटरनेशनल इवेंट्स से दूर रही थीं। तैयारी की कमी का असर उनके प्रदर्शन से जाहिर हो रहा था। उन्होंने स्नैच में 3 प्रयासों में केवल एक सफल लिफ्ट किया। पहले प्रयास में वे 84 केजी वेट लिफ्ट करने में फेल रहीं और दाहिने घुटने को पकड़ते दिखाई दीं। हालांकि दूसरे प्रयास में उन्होंने यही वजन आराम से उठा लिया। तीसरे प्रयास में उन्होंने 89 केजी उठाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सकीं।

क्लीन एंड जर्क में बेहतर प्रदर्शन – स्नैच के बाद क्लीन एंड जर्क की लिफ्टिंग हुई। चानू ने पहले अटैम्प्ट में 105 केजी उठाया। दूसरे प्रयास में उन्होंने 109चव वेट भी आसानी से उठा लिया। तीसरे प्रयास में चानू ने 113 केजी वेट उठाने की कोशिश की लेकिन विफल रहीं। इस तरह स्नैच में 84 केजी और क्लीन एंड जर्क में 109 चव की बेस्ट लिफ्ट के साथ चानू ने ओवरऑल 193 चव वेट उठाया और गोल्ड अपने नाम कर लिया। मलेशिया की आइरीन हेनरी ने कुल 161 केजी (73+88) उठाकर सिल्वर मेडल जीता, जबकि वेल्स की निकोल रॉबर्ट्स ने कुल 150 किलो (70+80) के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

49 केजी कैटेगरी से 48 केजी में शिफ्ट हुई हैं चानू – 31 वर्षीय चानू पहले 49 किलो वर्ग में वेटलिफ्टिंग करती थी। हालांकि पिछले ओलिंपिक में 49 किलो वर्ग हटा दिया गया, जिस वजह से उन्हें 48 किलो वर्ग में शिफ्ट होना पड़ा।

रिंकू ने 'कोहली स्टाइल' में प्रिया को दिया फ्लाइंग किस

लखनऊ में मैच देखने पहुंचीं, चुलबुल रोबोट ने सांसद के लिए बनाया दिल

लखनऊ (एजेंसी)। नोएडा के बाद लखनऊ में भी क्रिकेटर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की केमिस्ट्री दिखी। यहां इकाना में यूपी टी-20 लीग में रिंकू का मैच देखने सोमवार को सांसद प्रिया सरोज पहुंचीं। वह उनका ख्याल रखते नजर आते हैं। ठीक इसी अंदाज में रिंकू सिंह भी प्रिया सरोज का ख्याल रखते दिखाई दिए और प्यार भी जताया। मैच देखने पहुंची प्रिया सरोज चुलबुल डॉग कैमरे से भी मस्ती करती हुई दिखीं। उन्होंने कैमरे से हाथ मिलाया। इसके बाद कैमरे ने प्रिया के लिए दिल बनाया। इस दौरान उनसे नमस्ते भी किया।प्रिया ने इकाना में रिंकू का मैच देखा। वह बालकनी से मैच देख रही थीं। रिंकू जब पवेलियन में थे तो वह इन्हें निहार रहे थे।

लखनऊ में यूपी-टी 20 लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है। मेरठ मावेरिक्स और कानपुर सुपरस्टार्स के बीच सोमवार को खेले गए मैच को देखने के लिए मैदान पर रिंकू सिंह की मंगेतर सांसद प्रिया सरोज भी पहुंची थीं। इस दौरान बारिश से प्रभावित मैच का फैसला डकवर्थ-लुइस नियम से हुआ। इससे कानपुर को लीग के 16वें मैच में पहली जीत नसीब हुई।

ग्रेटर नोएडा में भी रिंकू को किया था चीयर यूपी टी-20 लीग के पहले मेरठ की टीम ग्रेटर नोएडा में प्रैक्टिस कर रही थी। यहां पर क्रिकेटर रिंकू सिंह से मिलने उनकी मंगेतर और सपा सांसद प्रिया सरोज ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम में पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने रिंकू सिंह और उनकी टीम मेरठ मावेरिक्स को चीयरअप किया। उन्होंने टीम से कहा था- इस बार फिर जीतना है। इसके बाद हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया और पवेलियन में वापस आ गईं।

वीवीआईपी लाउंज में काफी देर बैठी रहीं। इस दौरान रिंकू सिंह ड्रेसिंग रूम की बालकनी से प्रिया सरोज को झांकते हुए दिखाई दिए। उन्होंने विराट कोहली की स्टाइल में प्रिया को फ्लाइंग किस भी दिया।

इस दौरान रिंकू सिंह के फैंस ने उनका और प्रिया सरोज का अभिवादन राम-राम करके किया। इसपर रिंकू सिंह ने भी फैंस से राम-राम किया। वहीं, स्टेडियम के अंदर सांसद प्रिया सरोज के लिए चुलबुल रोबोट कैमरे ने दिल बनाया। उनके साथ हाथ मिलाकर चीयर भी किया। हालांकि रिंकू सिंह की टीम ये मैच हार गई।

चुलबुल डॉग कैमरे से प्रिया ने की मस्ती विराट कोहली की ऑन ग्राउंड अपने पत्नी अनुष्का शर्मा अक्सर फ्लाइंग किस देते और

अल्काराज यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे

ओपेल्का को सीधे सेटों में हराया, कैरोलिना मुचोवा से हारीं वीनस विलियम्स

स्पेन (एजेंसी)। स्पेन के टेनिस स्टार और यूएस ओपन में दूसरी सीड कार्लोस अल्काराज दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। वहीं, दो बार की चैंपियन वीनस विलियम्स को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए मैच में अल्काराज नए लुक में नजर आए। वह सिर मुंडवाकर खेलने उतरे। अल्काराज ने पहले राउंड में रीली ओपेल्का को 6-4, 7-5, 6-4 से हराकर शानदार जीत हासिल की। दो घंटे से ज्यादा समय तक चले इस मैच में उन्होंने केवल 17 गलतियां कीं, 58 में से 50 सर्विस पॉइंट जीते, सभी तीन ब्रेक पॉइंट बचाए और ओपेल्का की सर्विस तीन बार तोड़ी।अल्काराज ने पहले राउंड के मैच में रीली ओपेल्का को 6-4, 7-5, 6-4 से हराकर शानदार जीत हासिल की।

मैक्लॉरी ने नए लुक को लेकर किया मजाक - मैच से पहले अल्काराज की मुलाकात गोल्फ स्टार रॉरी मैक्लॉरी से हुई, जिन्होंने उनके मुंडे सिर को छूकर मजाक किया। पिछले हफ्ते यूएस ओपन के मिक्स्ड डबल्स में अल्काराज के बाल पूरे थे, लेकिन इस बार उनका नया लुक चर्चा का विषय बना।

मैच के बाद अल्काराज ने अपने हेयरकट के बारे में फेन्स की राय जानी - मैच के बाद अल्काराज ने दर्शकों से अपने नए हेयरकट के बारे में राय मांगी। दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ इसे पसंद किया। अल्काराज ने कहा, लगता है उन्हें मेरा नया लुक पसंद आया। हालांकि, उनके दोस्त और टेनिस खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो को यह हेयरकट बिल्कुल पसंद नहीं आया। टियाफो ने मजाक में कहा, यह भयानक है, जिसने भी कार्लोस को ऐसा करने को कहा, उसने गलत सलाह दी। मैं अच्छे हेयरकट का शौकीन हूं, लेकिन यह वाकई खराब है।

अवनीत कौर ने विराट कोहली के 'लाइक' पर तोड़ी चुप्पी, एक्ट्रेस ने कहा- प्यार मिलता रहे

नईदिल्ली (एजेंसी)। क्रिकेटर विराट कोहली ने कुछ महीने पहले एक्ट्रेस अवनीत कौर के फैन पेज की एक पोस्ट को लाइक कर दिया था। जिसके बाद इसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी। अब अवनीत ने इनडायरेक्टली इस पर बात की है। अवनीत की अपकमिंग फिल्म लव इन वियतनाम के ट्रेलर लॉन्च पर जब उनसे पूछा गया कि बड़े नामों से ऑनलाइन इतना ध्यान और तारीफ मिलना कैसा लगता है, तो मुस्कुराते हुए अवनीत ने कहा

प्यार मिलता रहे।अवनीत कौर की फिल्म लव इन वियतनाम 12 सितंबर, 2025 को रिलीज होगी। बता दें कि विराट कोहली ने मई के महीने अवनीत कौर की एक पोस्ट को लाइक किया था। हालांकि, थोड़ी ही देर बाद विराट ने उस लाइक को हटा दिया था, लेकिन इसी बीच विराट के लाइक का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। बाद में इस मामले में विराट को सफाई देनी पड़ी थी। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए लिखा था, 'मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि फीड क्लियर करते समय ऐसा लगता है कि ऐल्गोरिद्म ने गलती से कोई इंटरैक्शन रजिस्टर कर लिया है। इसके पीछे मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया बेवजह कोई भी बातें न बनाएं। समझने के लिए धन्यवाद।'

अंपायर का भी खराब दिन हो सकता है

क्रिकेट के इस नियम में बदलाव चाहते हैं सचिन तेंदुलकर

नई दिल्ली, एजेंसी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर चाहते हैं कि डिसिजन रिव्यू सिस्टम में अंपायर कॉल नियम में बदलाव चाहते हैं। तेंदुलकर ने सोमवार (26 अगस्त) को सोशल मीडिया साइट रेडिट पर फैंस से बातचीत में कही। इस दौरान उनसे सवाल हुआ कि क्रिकेट का कौन सा नियम वह बदलना चाहेंगे। इस पर उन्होंने अंपायर्स कॉल का नाम लिया। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि खिलाड़ी मैदान पर मौजूद अंपायर के फैसले से नाखुश होने के कारण डीआरएस लेता है, ऐसे में उनका मानना है कि उस फैसले को बरकरार रखने का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। आस्क मी एनीथिंग (क्र) सेशन के दौरान तेंदुलकर ने कहा, मैं अंपायर कॉल को लेकर डीआरएस नियम बदलूंगा। खिलाड़ियों ने थर्ड अंपायर के पास जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वे मैदान पर मौजूद अंपायर के फैसले से नाखुश थे। इसलिए उस फैसले को बरकरार रखने का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। जिस तरह खिलाड़ियों का खराब समय होता है। उसी तरह अंपायरों का भी खराब समय होता हैं। तकनीक भले ही गड़बड़ हो वह गड़बड़ ही रहेगी।

पहले भी अंपायर कॉल की आलोचना कर चुके हैं तेंदुलकर

यह पहला मौका नहीं था कि सचिन तेंदुलकर ने अंपायर कॉल को हटाया जाना चाहए। 2020 में उन्होंने कहा था कि अगर बॉल ट्रैकिंग के दौरान गेंद जरा सा भी स्टंप पर लगती है तो आउट दिया जाना चाहिए। उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा के साथ एक वीडियो चैट में कहा था, मैं आईसीसी के डीआरएस से सहमत नहीं हूं,जिसका इस्तेमाल काफी समय से हो रहा है। एलबीडब्ल्यू के मामले में मैदान पर लिए गए फैसले को पलटने के लिए गेंद का 50व से ज्यादा हिस्सा स्टंप्स पर लगनाजरूरी है। वे (बल्लेबाज या गेंदबाज) सिर्फ इसलिए ऊपर गए हैं क्योंकि वे मैदान पर लिए गए फैसले से नाखुश हैं, इसलिए जब फैसला तीसरे अंपायर के पास जाए तो तकनीक को अपना काम करने दें। बिल्कुल टेनिस की तरह या तो इन या आउट होना चाहिए। बीच का रास्ता नहीं होना चाहिए।

अंपायर कॉल क्या है?

अंपायर कॉल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब डीआरएस तकनीकी साक्ष्य निर्णायक न होने की स्थिति में मैदान पर लिए गए फैसले को 'संदेह का लाभ' देता है। बॉल-ट्रैकिंग तकनीक के अनुसार जब गेंद का 50व से कम हिस्सा (बेल्स को छोड़कर) स्टंप्स पर लग रहा हो तो यह अंपायर कॉल होता है। हालांकि, ऐसी स्थिति में टीमें अपने रिव्यू नहीं गंवाती।

एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के आठवें दिन भारत को 8 मेडल

महिला ट्रैप टीम और इंडिविजुअल में नीरू धनदा और जूनियर पिस्टल में पायल ने गोल्ड जीता

शिमकेंट (एजेंसी)। कजाकिस्तान के शिमकेंट में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के आठवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। महिला ट्रैप इवेंट में भारत ने इंडिविजुअल और टीम दोनों इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। नीरू धनदा ने इंडिविजुअल में गोल्ड जीता, जबकि जूनियर महिला 25 मीटर पिस्टल में भी भारत ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया।

महिला ट्रैप में मिले तीन मेडल - महिला ट्रैप इवेंट में भारत को तीन मेडल मिले। नीरू धनदा और आशिमा अहलावत ने क्वालिफिकेशन में 107 अंकों के साथ पांचवें और छठे स्थान पर जगह बनाई। प्रीति रजक 105 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में बाहर हो गईं। कतर की रे बासिल ने 110 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहीं। फाइनल में नीरू ने शानदार प्रदर्शन किया। शुरुआत में भारत की नीरू और आशिमा, कतर की रे बासिल और जापान की नामी मियासाका के बीच कड़ा मुकाबला रहा। बाद में चीनी ताइपे की लियू वान-यू भी चुनौती बनकर उभरीं। नीरू ने अंतिम 25 में से 22 और आखिरी 10 टारगेट्स में सभी 10 हिट्स लगाए, जिससे उन्होंने 43 हिट्स के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आशिमा और रे बासिल 29 हिट्स के साथ बराबरी पर रहीं, लेकिन बिब नंबर के आधार पर आशिमा को ब्रॉन्ज और रे को सिल्वर मिला। भारत की तिकड़ी (नीरू, आशिमा, प्रीति) ने 319 अंकों के साथ टीम गोल्ड भी जीता, जो चीन (301) से 18 अंक आगे रहा।

जूनियर महिला 25 मीटर पिस्टल में तीनों मेडल भारत - जूनियर महिला 25 मीटर पिस्टल में भारत की पायल खत्री, नाम्या कपूर और तेजस्विनी ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में तीनों भारतीय खिलाड़ियों ने कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया की प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए आपस में ही मुकाबला किया। पायल ने छठे से नौवें सीरीज में चार-चार हिट्स और 10वीं सीरीज में 5/5 हिट्स के साथ 36 हिट्स बनाए और गोल्ड जीता।

पाकिस्तान से क्रिकेट? सुशील दोषी बोले, बिल्कुल नहीं

क्रिकेट सभ्य खेल है; आतंकवाद असभ्य हरकत, पाकिस्तान को क्रिकेट से अलग-थलग करना जरूरी

भोपाल (एजेंसी)। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, जिसको लेकर देशभर में एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच दिग्गज रेडियो कमेंटेटर और पद्मश्री सुशील दोषी ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने को लेकर बड़ा बयान दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि क्रिकेट सभ्य लोगों का खेल है और आतंकवाद असभ्य हरकत। ऐसे में सभ्य खेल में असभ्य लोगों को कोई जगह नहीं हो सकती। दोषी ने कहा-मैं तो ये सोचता हूं कि अगर आप आतंकवाद फैलाते हो और दूसरी तरफ क्रिकेट खेलते हो, तो ये साथ-साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान के साथ न खेलकर हमें उसे क्रिकेट से अलग-थलग करना चाहिए। सुशील मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी का वार्षिक अलंकरण समारोह में अलंकृत होने के लिए सोमवार को भोपाल पहुंचे थे। दोषी ने कहा- आप दुनिया को कैसे समझा सकते हैं कि हॉकी तो खेलेंगे, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे, टेनिस खेलेंगे लेकिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे, विदेशों में जाकर खेलेंगे लेकिन पाकिस्तान से क्रिकेट खेलेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। करना ये चाहिए कि भारत न सिर्फ खुद पाकिस्तान का बहिष्कार करे बल्कि दुनिया के देशों को भी इसके लिए प्रेरित करे।

भारत के पास है ताकत, पाकिस्तान को कर सकता है मजबूर - दोषी ने भारत की ताकत और जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा आज भारत क्रिकेट का सुपर पावर है। हमारे पास इतनी ताकत है कि अपनी इच्छा से लोगों को मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसलिए भारत को चाहिए कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे और दुनिया से भी पाकिस्तान का अलग-थलग करने के लिए कहे। इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। उन्होंने कहा-कहते हैं ना, उस जगह को दबाओ जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द तब होगा जब क्रिकेट में उसे अलग-थलग कर दिया जाएगा। जब भारत उसके साथ नहीं खेलेगा तो यह सबसे बड़ा संदेश होगा।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे शिवराज सिंह चौहान?

● मोहन भागवत से मीटिंग के बाद अटकलें तेज

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर अब तक मुहर नहीं लग सकी है। साथ ही पार्टी की तरफ से कोई तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव का शेड्यूल आने से पहले अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। साथ ही आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख प्रमुख मोहन भागवत के साथ केंद्रीय मंत्री की

मुलाकात ने अटकलें तेज कर दी हैं। हालांकि, भाजपा की तरफ से आधिकारिक तौर पर साफ नहीं किया गया है कि अगले प्रमुख के नाम की घोषणा कब होगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र बताते हैं कि पार्टी आलाकमान की तरफ से संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गई है। वहीं, इस पर 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव की जानकारी दी जा सकती है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों के प्रमुख पहले चुने जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने यह भी कहा है कि अगर अध्यक्ष बिहार चुनाव की घोषणा से पहले नहीं चुना गया, तो नियुक्ति चुनाव के बाद ही की जाएगी।

डीयू को गर्व नहीं है क्या कि मोदी उनके यहां पढ़े थे

पीएम के डिग्री विवाद पर आतिशी

नई दिल्ली, एजेंसी। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री अब सार्वजनिक नहीं की जाएगी। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश को खारिज कर दिया है। अब इसपर राजनीति भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी ने तो आज सुबह सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी रेड को भी इससे जोड़ दिया। कहा कि ये सब पीएम मोदी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। आतिशी ने आज इसपर प्रेस कॉन्फ्रेंस

कर अपना और सीएम रेखा गुप्ता का उदाहरण दिया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पूछ लिया कि क्या आपको गर्व नहीं है क्या कि पीएम आपके यहां पढ़े थे। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक आरटीआई कार्यकर्ता को केंद्रीय सूचना आयोग से यह आदेश मिला था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाए। डिग्री दिखाने की बजाय, यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। उन्होंने आगे कहा, पूरा देश जानना चाहता है कि यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व क्यों नहीं है कि उसका एक छात्र प्रधानमंत्री है। पूरा देश इसी बारे में बात कर रहा था। इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, सौरभ भारद्वाज के घर पर फर्जी ईडी छापे मारे जा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि आखिर यह कैसी यूनिवर्सिटी है, जिसे इस बात का गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री उसके पूर्व छात्र हैं। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का उदाहरण देते हुए कहा कि जब रेखा गुप्ता सीएम बनीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन्हें बकायदा बुलाकर सम्मानित किया।

सौरभ भारद्वाज पर ईडी रेड से बुरी तरह भड़के अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। सौरभ भारद्वाज पर कथित अस्पताल घोटाला मामले में आज सुबह ईडी की रेड के बाद एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने-सामने हो गए हैं। आप के कई नेता इसे पीएम मोदी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए की गई कार्रवाई करार दे रहे हैं। अब इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन सामने आया है। केजरीवाल ने सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। मोदी सरकार हमारी आवाज

दबाना चाहती है। ये कभी नहीं होगा।

ईडी रेड पर क्या बोले केजरीवाल?- अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज पर हुई ईडी की रेड के खिलाफ कहा कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडीकी रेड मोदी सरकार की ओर से एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आप को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि आप को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आप की है। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। ये कभी नहीं होगा। आप बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं।

आतिशी और सिसोदिया ने पीएम मोदी की डिग्री से जोड़ा लिंक

नेता विपक्ष और कालकाजी विधायक आतिशी ने लिखा कि आज सौरभ जी के यहां रेड क्यों हुई? क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं,क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है। जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे। यानी पूरा केस ही झूठा है। सत्येंद्र जी को भी तीन साल जेल में रखकर आखिरकार सीबीआइ/ईडी को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ़ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठ और राजनीति से प्रेरित हैं। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि कल पूरे देश ने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया...जब डिग्री का सच सामने आया तो ध्यान भटकाने के लिए आज सौरभ भारद्वाज पर ईडीकी रेड कराई जा रही है। सवाल साफ था कि क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? लेकिन उस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड डाल दी गई। सिसोदिया ने लिखा कि जिस दौर का ये केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ मंत्री थे ही नहीं। इसका सीधा मतलब है कि जैसे इनकी डिग्री फ़र्ज़ी है वैसे ही केस भी फर्जी हैं। याद कीजिए सत्येंद्र जैन को। तीन साल जेल में रखा गया, सीबीआइ और ईडीने दिन-रात खंगाला, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सच्चाई ये है कि ये सारे केस फर्जी हैं। असली लड़ाई सच्चाई की नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी को दबाने की है।

तब तो वह मंत्री भी नहीं थे; सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पर संजय सिंह की दलील

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर चल रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी से 'आप' भाजपा पर आग बबूला है। 'आप' के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी का यह मामला पूरी तरह से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है, क्योंकि यह जिस वक्त यह केस बनाया गया, उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमें झुकाने के लिए 'आप' नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाना भाजपा सरकार की नीति बन गई है।

सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पर जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरह से झूठा, निराधार और बेबुनियाद है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यह जिस वक्त यह केस बनाया गया, उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। एक झूठा और बेबुनियाद केस बनाकर सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही हैज आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार झूठे केस बना-बनाकर उन्हें जेल में डालना भाजपा और मोदी सरकार की एक नीति बन गई है। उनका एक रवैया बन गया है, हमको दबाने और हमको झुकाने के लिए।

'आप' सांसद ने आगे कहा, यह सब कुछ आज क्यों हो रहा है, क्यों सौरभ भारद्वाज के घर आज छापा मार दिया गया। क्योंकि खबर बदली है।

दिल्ली-एनसीआर में बीपीटीपी के ठिकानों पर ईडी की धमाकेदार छापेमारी, विदेशी निवेश से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी बीपीटीपी के कई ठिकानों पर छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEM) के तहत की गई, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश से जुड़े उल्लंघन का मामला सामने आया है।

कंपनी के CMD पर गंभीर आरोप- ईडी के सूत्रों ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि बीपीटीपी के CMD काबुल चावला पर विदेशों में गुपचुप तरीके से संपत्ति रखने का आरोप है। इतना ही नहीं, कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर के कई पुलिस स्टेशनों में दर्ज FIRs भी ED की जांच के दायरे में हैं। यह मामला अब और गहराता जा रहा है।

बीपीटीपी की चुप्पी- ED की इस बड़ी कार्रवाई पर बीपीटीपी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन जवाब का इंतजार है। क्या यह चुप्पी तूफान से पहले की शांति है? ईडी की इस छापेमारी ने रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी है। सूत्रों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

क्या है मामला?

ईडी की ताजा जांच में पता चला है कि फरीदाबाद की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी बिजनेस पार्क्स टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2007-08 के दौरान मॉरीशस की कंपनियों से 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का विदेशी निवेश हासिल किया। लेकिन यह निवेश ऑटोमैटिक रूट के जरिए लिया गया, जो FEMA नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने पुट ऑप्शन/स्वैप ऑप्शन के जरिए यह निवेश हासिल किया, जो नियमों के खिलाफ था।

व्यापार खड़ा करने में युवाओं की मदद करेगी सरकार, दिल्ली की नई स्टार्टअप नीति का ड्राफ्ट तैयार

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी में युवा उद्यमी तैयार करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार पांच हजार नए स्टार्टअप को मदद देगी। इन स्टार्टअप को न सिर्फ वित्तीय सहायता, बल्कि फिक्की, सीआईआई जैसे बड़े औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर स्टार्टअप को मार्गदर्शन भी दिलाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए नई स्टार्टअप नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति के तहत सरकार का फोकस स्टार्टअप को निवेश और ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने पर होगा। दिल्ली सरकार की नई स्टार्टअप नीति के तहत महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह नीति 10 साल के लिए लागू की जाएगी और इसके तहत 2025 से 2035 तक पांच हजार स्टार्टअप को मदद देकर उन्हें न सिर्फ खड़ा करना है बल्कि यूनिकॉर्न बनाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इसका मकसद राजधानी के लिए न सिर्फ नवाचार पर आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, बल्कि दिल्ली को स्टार्टअप का वैश्विक हब बनाना भी है।

दिवाली-छठ पर यूपी-बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटें अभी से फुल

फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ा

नई दिल्ली, एजेंसी। दिवाली एवं छठ पर्व मनाने के लिए यूपी-बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए अधिकतर रेलगाड़ियों में रिजर्वेशन वाली टिकटें खत्म हो चुकी हैं। ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं बन रही हैं। कुछ गाड़ियों में वेटिंग टिकट उपलब्ध भी हैं तो उनके कन्फर्म होने की संभावना न के बराबर है। ऐसे में विमान कंपनियों ने भी अपना किराया 17 से 24 अक्टूबर तक लगभग दो से तीन गुना तक कर दिया है।

हर साल दिवाली एवं छठ पर्व के मौके पर दिल्ली से लाखों लोग बिहार, झारखंड, यूपी के विभिन्न शहरों के लिए सफर करते हैं। आगामी 21 अक्टूबर को दिवाली, जबकि 27-28 को छठ पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में 60 दिन पहले रेलगाड़ी के लिए टिकट की बुकिंग सुबह खुलते ही चंद मिनटों में पूरी हो जा रही है। बिहार जाने वाली अधिकांश रेलगाड़ियों में 17 से 24 अक्टूबर तक एक भी सीट नहीं मिल रही है।

बिहार के जयनगर, दरभंगा, पटना आदि के लिए चलने वाली रेलगाड़ियों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रही है। झारखंड जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में भी टिकट का यही हाल है। वाराणसी एवं प्रयागराज जाने वाली कुछ गाड़ियों में 18-19 अक्टूबर की सीट नहीं हैं, लेकिन 20-22 अक्टूबर की कुछ सीटें बची हुई हैं।

विमान कंपनियों ने भी किराया बढ़ा दिया है। दिल्ली से पटना, दरभंगा, गया, आदि रूटों पर विमानों में दो से तीन गुना तक किराया वसूला जा रहा है। गौरतलब है

कि रेलवे की ओर से आवश्यकता पड़ने पर अनारक्षित रेलगाड़ियों का भी परिचालन किया जाएगा। यह गाड़ियां दिवाली एवं छठ के आसपास ही अधिक संख्या में चलाई जाती हैं। हाल ही में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि त्योहारों के समय 12 हजार विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। यह देश के अलग-अलग हिस्सों से पूर्व के शहरों को जोड़ेंगी।

तो बढ़ जाएगा आईफोन का दाम?

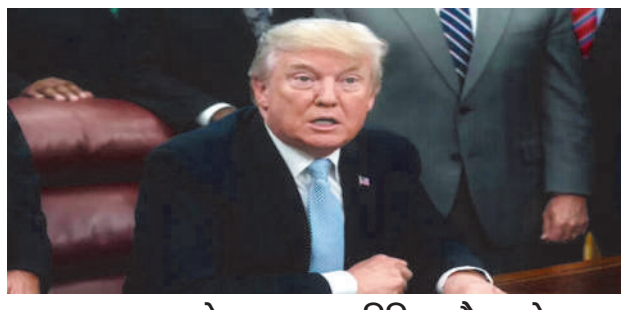

गूगल-अमेजन पर लगा डिजिटल टैक्स तो ट्रंप को लगी मिर्ची, इन देशों को दी धमकी

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को धमकी दी है। सोमवार को उन्होंने धमकी दी कि जो भी देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स या उससे जुड़े नियम लगाएंगे, उनके खिलाफ अमेरिका भारी-भरकम टैरिफ लगाएगा और चिप निर्यात पर रोक लगाएगा।

ट्रंप का यह बयान उन देशों के लिए सख्त संदेश है, जो अल्फाबेट, मेटा और अमेजन जैसी अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनियों पर टैक्स लगा रहे हैं।

चीन की कंपनियों को मिल रहा छूट और हमें...: ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर तल्ख लहजे में कहा कि वह अमेरिका की शानदार टेक कंपनियों के खिलाफ होने वाले किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि डिजिटल टैक्स, डिजिटल सर्विस नियम और डिजिटल मार्केट रेगुलेशन अमेरिकी टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचाने और भेदभाव करने के लिए बनाए गए हैं।

ट्रंप ने गुस्से में यह भी कहा कि ये नियम चीन की बड़ी टेक कंपनियों को पूरी तरह छूट देते हैं, जो बिल्कुल नाकाबिले-बर्दाश्त है।

हम अपने कीमती टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट पर लगाएंगे प्रतिबंध: उन्होंने लिखा, डिजिटल टैक्स, डिजिटल सर्विस कानून और डिजिटल मार्केट नियम अमेरिकी टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचाने और भेदभाव करने के लिए बनाए गए हैं। वे, बेशर्मी से, चीन की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को पूरी छूट देते हैं। यह अब बंद होना चाहिए और अभी बंद होना चाहिए! उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका अपनी बेहद कीमती टेक्नोलॉजी और चिप्स पर निर्यात प्रतिबंध भी लगाएगा। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी, मैं उन सभी देशों को, जो डिजिटल टैक्स, कानून, नियम या रेगुलेशन लागू करते हैं, नोटिस देता हूं कि अगर ये भेदभावपूर्ण कदम नहीं हटाए गए, तो मैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, उनके देश के अमेरिका में होने वाले निर्यात पर भारी अतिरिक्त टैरिफ लगाऊंगा।

प्रधानमंत्री अल्बनीज का सनसनीखेज आरोप- ईरान ने ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमले करवाए

सिडनी, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाया कि उसने ऑस्ट्रेलिया में कम से कम दो यहूदी विरोधी हमलों को अंजाम देने का निर्देश दिया। अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई खुफिया सेवाओं के मुताबिक, सिडनी के एक रेस्टोरेंट और मेलबर्न की एक मस्जिद पर हुए हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ईरानी राजदूत को निष्कासित कर रहा है।

ईरान सरकार ने दिए हमलों के आदेश : अल्बनीज ने खुफिया एजेंसी का हवाला देते हुए बताया कि ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन ने विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर एक चिंताजनक निष्कर्ष निकाला है। कम से कम दो हमलों का निर्देश ईरान सरकार ने दिया था। ईरान ने अपनी संलिप्तता को छिपाने की कोशिश की, लेकिन एएसआईओ का मानना है कि इन हमलों के पीछे ईरान ही था। उन्होंने कहा कि पिछले साल 20 अक्टूबर को सिडनी के लुईस कॉन्टिनेंटल किचन और 6 दिसंबर को मेलबर्न के अदास इजराइल सिनागॉग पर हुए हमलों में ईरान की भूमिका थी, जिसे उसने छिपाने की कोशिश की।

सामाजिक एकता को तोड़ने की साजिश : अल्बनीज ने कहा कि एएसआईओ के अनुसार, संभव हो कि ईरान ने और हमलों की योजना बनाई हो। उन्होंने इसे ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एक विदेशी राष्ट्र द्वारा रची गई असाधारण और खतरनाक आक्रामकता करार दिया। ये हमले सामाजिक एकता को कमजोर करने और समुदाय में विभाजन पैदा करने की कोशिश थे। अल्बनीज ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान स्थित अपने दूतावास का कामकाज स्थगित कर दिया है और सभी राजनयिक किसी तीसरे देश में सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनकी सरकार तेहरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन घोषित करेगी।

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर हुई चर्चा

अल्जीयर्स, एजेंसी। सेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को अपनी आधिकारिक अल्जीरिया यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया और भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने को लेकर बातचीत की। जनरल द्विवेदी ने अल्जीरियाई थल सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोस्तेफा समाली से मुलाकात की। उन्होंने भारत और अल्जीरिया की सेनाओं के बीच आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की।

भारतीय सेना के जनसंपर्क निदेशालय (एडीजी-पीआई) ने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अल्जीयर्स स्थित थल सेना कमान मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया और फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोस्तेफा समाली के साथ बातचीत की। बातचीत का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना, शांति और सुरक्षा के प्रति आपसी प्रतिबद्धता को मजबूत करना था।

अपनी यात्रा की शुरुआत जनरल द्विवेदी ने सोमवार को अल्जीरिया में भारत की राजदूत स्वाति विजय कुलकर्णी की ओर से आयोजित स्वागत रात्रिभोज के साथ की। इस कार्यक्रम में अल्जीरियाई गणमान्य व्यक्तियों, विभिन्न देशों के राजदूतों, रक्षा अधिकारियों, वाणिज्य मंडलों के प्रमुखों, थिंक टैंक और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। जरनल द्विवेदी से पहले हाल ही में भारत की राष्ट्रपति और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) भी अल्जीरिया की यात्रा कर चुके हैं।

हाइब्रिड मॉडलों को पसंद कर रहे कर्मचारी

सर्वे में सामने आई लोगों के मन की बात

क्वींसलैंड , एजेंसी। वर्क फ्राम होम के बाद आफिस जाने पर यदि आपको भी तनाव होता है तो आप अकेले नहीं है। दरअसल, महामारी के दौरान की गई इस व्यवस्था ने लोगों को न सिर्फ इसका आदी बना दिया बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो घर से बेहतर परिणाम देने की स्थिति में आ गए।

हाल ही में बॉन्ड विश्वविद्यालय की ओर से वर्फ फ्रॉम होम को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों का विश्लेषण किया गया जिसमें सामने आया कि कोविड के बाद कार्यालय लौटने की दरें जून 2023 के आसपास स्थिर हो गईं और तब से इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है।

सर्वे में ये बात आई सामने: निष्कर्ष में पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में अगस्त 2024 में 36 प्रतिशत लोग नियमित रूप से घर से काम कर रहे थे जबकि 2023 में यह आंकड़ा 37 प्रतिशत था। यह महामारी से पहले के स्तरों से एक नाटकीय बदलाव है जब केवल पांच प्रतिशत ही नियमित रूप से घर से काम करते थे।

वहीं, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लगभग 30 प्रतिशत कर्मचारी अब हाइब्रिड शेड्यूल पर काम कर रहे हैं जबकि 2020 से पहले ये प्रतिशत न्यूनतम था।

हाइब्रिड मॉडलों को पसंद कर रहे कर्मचारी: वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड माडलों पर शोध से सामने आया कि इस माध्यम से कार्य-जीवन संतुलन में सुधार किया जा सकता है और कर्मचारियों की कमी की दर को भी कम किया जा सकता है।

2024 में किए गए एक परीक्षण में पाया गया था कि हाइब्रिड कार्य व्यवस्थाओं के

कारण 33 प्रतिशत कम छोड़ने की दरें थीं। इसके अलावा व्यक्तिगत उत्पादकता को ट्रैक करने वाले शोध में पाया गया कि पूरी तरह से दूरस्थ कार्य उत्पादकता में 10 प्रतिशत की कमी से जुड़ा था। सामने आया कि कर्मचारी आमतौर पर हाइब्रिड मॉडलों को पसंद कर रहे थे।

ऑफिस और घर दोनों जगह से काम करने का विकल्प चाहते हैं युवा: शोधकर्ताओं ने निदान के तौर पर बताया कि कर्मचारियों को कार्यालय लौटने के लिए धीरे-धीरे वापस आने की अनुमति दें। क्रमिक परिवर्तन अचानक बदलाव की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं।

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रकः- देवेन्द्र मालवीय द्वारा श्री सिंध्दी विनायक प्रिंटर्स 26 बी देशबंधु परिसर प्रेस काम्प्लेक्स झोन 1 एम पी नगर भोपाल म.प्र. से मुद्रित एवं 773 / 19 मेघदूत नगर इंदौर म.प्र. से प्रकाशित सम्पादक डॉ. देवेन्द्र मालवीय
कार्यालय पताः-एच. 21 अंकित अपार्टमेंट ब्रजेश्वरी एनएक्स, इंदौर मध्यप्रदेश मोः- 98276-22204 सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इंदौर रहेगा। डाक पंजीकरण संख्या-MP/IDC/1619/2024-2026

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सूचनाए, विचार,आलेख विभिन्न समाचार के स्त्रोत एवं संकलन लेखकों के व संकलनकर्ता के स्वंय जिनका संकलन विभिन्न एजेंसियों, के माध्यम से किया गया है, अतः समस्त प्रकार के प्रकाशन हेतु संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहमत होना अनिवार्य नही है।